RNI No : JHAHIN/2021/83133

वर्ष- चार, अंक-01, अप्रैल- 2024 मूल्यः 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

दो चरणों का चुनाव संपन्न

मतदाताओं का मत ईवीएम में बंद

परिवार से मिलती है ताकत, पोतियां है सबसे बड़ी दौलत : गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अपनी पोती के बारे में कहा है कि कोई भी दौलत इनकी आंखों की चमक की बराबरी नहीं कर सकती। कावेरी, उनकी सबसे छोटी पोती और परिधि और करण अदाणी की तीसरी बेटी हैं। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, "इन आंखों की चमक की तुलना में दुनिया की सारी दौलत फीकी है।" ये तस्वीर नई अदाणी ग्रीन गैलरी के दौरे पर लंदन साइंस म्यूजियम में ली गई है।

हाल ही में, एक कार्यक्रम में गौतम अदाणी ने कहा था कि अपनी पोतियों के साथ समय बिताना उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। गौतम अदाणी कहते है, "मुझे अपनी पोतियों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। इससे सारा तनाव दूर हो जाता है। मेरी सिर्फ दो दुनिया है, काम और परिवार। मेरा परिवार ही मेरी ताकत है।"

माता-पिता से मिली प्रेरणा : शुरुआती सालों में गौतम अदाणी अपने माता-पिता से प्रभावित और प्रेरित थे। उन्होंने कहा, "मेरी मां हमारे घर का पिलर थीं. उन्होंने हमारी ज्वाइंट फैमिली को मजबूती से जोड़े रखा। हमारे बड़े परिवार को एक साथ रखने की उनकी प्रतिबद्धता ने मेरे अंदर पारिवारिक मूल्यों और विश्वासों की नींव रखी। मेरे पिता बिजनेसमैन थे, उन दिनों लेन-देन मौखिक रूप से होता था या फिर ज्यादातर टेलीफोन पर ही होता था। पहले लिखित दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे. बहुत कम उम्र में मैंने देखा कि मौखिक प्रतिबद्धताएं कभी फेल नहीं होती।" गौतम अदाणी कहते हैं, "मेरे बचपन के इन अनुभवों ने मेरे विश्वासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी का परिणाम है आज अदाणी ग्रुप की कोर वैल्यू में लोगों में विश्वास बढ़ा है "

अदाणी समूह किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है : गौतम अदाणी भले ही अदाणी समूह के फाउंडर हैं, लेकिन आज ये समूह किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। अदाणी सिर्फ एक नाम या ब्रांड से कहीं अधिक है। अदाणी एक कल्चर है। यह एक विचारधारा है। यह सोचने का एक तरीका है। समूह के बारे में गौतम अदाणी बताते है कि "मुझे और आने वाली पीढ़ी को इसपर गर्व तो होता ही है साथ ही इससे एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इससे कर्मचारियों और प्रमोटर्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। यह एकजुटता की ताकत है जो अदाणी समूह को एक मजबूत अदाणी परिवार बनाती है। यह हमारे कैन-डू-ऐटिट्यूड का हिस्सा है। हम सादगी में भरोसा रखते हैं, और जहाँ एक तरफ हमें अपने काम पर गर्व है, वहीं हम अपनी उपलब्धियों के बारे में विनम्र रहने में भी विश्वास रखते हैं।"

मुंबई में अदाणी बदलेंगे धारावी की तस्वीर

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी के हाथों में मुंबई की सूरत बदलने की जिम्मेदारी है. अदाणी वो कर सकते हैं, जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अदाणी समूह ने ग्लोबल टीम तैयार की है। अदाणी ने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। समूह की कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े स्लम धारावी की सूरत बदलने के लिए अमेरिका की डिजाइनिंग टीम हायर की। इसके अलावा ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म और आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ हाथ मिलाया है साथ ही उन्होंने सिंगापुर के एक्सपर्ट को इस प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ जोड़ा है. दुनिया की टॉप ग्लोबल टीमों को अपने साथ जोड़कर अदाणी धारावी की सूरत बदल देंगे.

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

Web : navjeewansandesh.com

संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)

▪ वर्ष -3, ▪ अंक -12, ▪ कुल पृष्ठ -36

index

प्रधान संपादक

पंकज कुमार सिंह

संपादक

प्रभात मजुमदार

संपादक मंडल

जगन्नाथ मुंडा

सुनीता सिन्हा

श्रीमती छाया

रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी

चंचल भट्टाचार्य

मुख्यसंवाददाता

सत्येंद्र सिंह

छायाकार

नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799

9835437102

ईमेल: navjeewansandesh@gmail.com

पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम ... पेज-11

नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के तीन दर्जन .... पेज-08

लालू की रणनीति एनडीए ... पेज-22

झारखंड को हॉकी का गढ़, बनेगा और भी मजबूत .... पेज-32

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी।,बी। कॉर्प लि। प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।

संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)

आरएनआई नं.: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

1970 के दशक के बाद से संसद में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या लगभग आधी

उत्तर प्रदेश के रामपुर में आधे से अधिक मतदाता मुसलमान हैं, लेकिन इसके संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से आते हैं, जिस पर हिंदूवादी राजनीति करने की बात कही जाती है. यह स्थिति पूरे हिंदू-बहुल देश में दोहराई जाती दिख रही है, जहां कई लोग आगामी आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जीत को लगभग निश्चित मानते हैं और मुसलमान उम्मीदवारों की हार करीब-करीब तय मानते हैं.

भारत की कुल 1.4 अरब आबादी में मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ है, लेकिन 1970 के दशक के बाद से संसद में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या लगभग आधी होकर पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है.

रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी कहते हैं, "हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है." 2022 में हुए उप चुनाव में लोधी ने यह सीट जीती थी. लोधी कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया.

मुसलमान नेता संसद में प्रतिनिधित्व की कमी से चिंतित हैं. संसद के 543 सीटों वाले निचले सदन में सिर्फ 27 मुस्लिम सांसद थे और उनमें से कोई भी बीजेपी के 310 सांसदों में से नहीं था.

'मुस्लिम्स इन इंडिया' के लेखक जिया उस सलाम कहते हैं कि समुदाय के सदस्यों ने दशकों से धर्मनिरपेक्ष पार्टियों पर भरोसा जताया है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने "मुस्लिम नेतृत्व की तेज अनुपस्थिति" पैदा की.

आज एक खुले तौर पर मुस्लिम नेता को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के रूप में चुनौती दी जाएगी, फिर भी जब मोदी संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भारत को "हिंदू राष्ट्र" या हिंदू राज्य के रूप में प्रचारित करते हैं तो कुछ ही लोग सवाल उठाते हैं.

सलाम कहते हैं, "कोई भी (मोदी के) केवल हिंदुओं का नेता होने की बात नहीं करता." वो यह भी दलील देते हैं कि पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए चुनावी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया.

1952 से अब तक रामपुर से 18 में से 15 बार मुसलमान सांसद चुने गए हैं. लेकिन शहर के 71 साल के एक्टिविस्ट और लेखक कंवल भारती कहते हैं कि बीजेपी के प्रभुत्व का मतलब है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार के लिए रामपुर जीतना "अब संभव नहीं लगता."

रामपुर के आखिरी मुसलमान सांसद कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान थे, लेकिन उनके खिलाफ जमीन हड़पने से लेकर सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने तक के 80 से अधिक मामले आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था.

उनके समर्थकों का कहना है कई आरोप वर्षों पुराने थे और 2017 में बीजेपी के राज्य चुनाव जीतने के बाद ही आरोप देर से लगाए गए थे. आजम खान को 2023 में हेट स्पीच के मामले में सजा हुई थी.

पिछले चुनाव में यह आरोप लगे थे कि सुरक्षा बलों ने मुसलमानों को मतदान करने से रोक दिया था. इस बार रामपुर के कुछ मुस्लिम मतदाता वोट डालने को लेकर चिंतित हैं. 75 साल के मोहम्मद सलाम खान कहते हैं, "अगर पिछले चुनाव के दौरान की स्थिति दोहराई गई, तो मैं फिर से वोट नहीं डाल पाऊंगा."

एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यह एक व्यापक बदलाव का हिस्सा है. ओवैसी का मानना है कि धर्मनिरपेक्ष दल भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे हिंदू मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे.

सत्ताधारी दल पर मुसलमानों के खिलाफ डर पैदा करने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा, "वे एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने से भी डरते हैं."

ओवैसी कहते हैं, "किसी भी राजनीतिक दल के मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए जीतना बहुत मुश्किल है."

बीजेपी धर्म के आधार पर "सीधे भेदभाव" से इनकार करती है और कहती है कि टिकट देना चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर निर्भर करता है. पिछले दो आम चुनावों में बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे गए मुट्ठी भर मुस्लिम उम्मीदवार हार गए थे. आलोचक पार्टी पर उनके चुनाव प्रचार में उदासीनता दिखाने का आरोप लगाते हैं.

बीजेपी के प्रवक्ता महोनलुमो किकोन कहते हैं, "आदर्श रूप से हमारी यह उम्मीद है कि हर समुदाय के लोग इसमें शामिल हों."

लेकिन लेखक सलाम को लगता है कि मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है. वह कहते हैं, "इसलिए, आप मुसलमानों को एक जगह से टिकट नहीं देते हैं, आप किसी अन्य स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र दोबारा बनाते हैं... या आप मुसलमानों को वोट देने की अनुमति नहीं देते हैं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "यह सिर्फ डराना-धमकाना नहीं है. यह उन्मूलन भी है."

बीजेपी के 'संकल्प पत्र' में यूसीसी से लेकर 'वन नेशन वन इलेक्शन'

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने घोषणा पत्र को 'भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी' नाम दिया है. भाजपा अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' कहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणापत्र जारी किया. देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है. पीएम मोदी ने पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा, "हमने संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है. लोगों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बनाने के लिए देशभर से सुझाव भेजे हैं.'' पीएम मोदी ने कहा, "पूरे देश को बीजेपी के घोषणापत्र का इंतजार रहता है. इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है.'' "ये संकल्प पत्र चार वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है. हमने बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ाने की बात की है. युवा भारत की युवा उम्मीदों की छवि बीजेपी के घोषणापत्र में है.'' पीएम मोदी ने आगे कहा, "25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाकर हमने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं. हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं.'' यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी इसे बेहद ही महत्वपूर्ण मानती है.

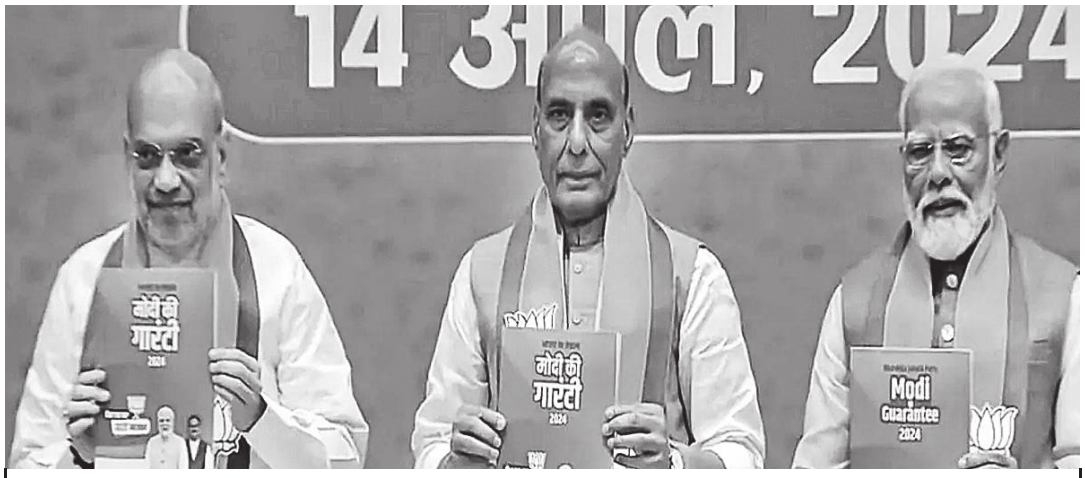

घोषणापत्र की खास बातें

- अगले पांच सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से जीरो बिजली बिल की व्यवस्था.
- आयुष्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, यह आगे भी मिलता रहेगा. 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को इस योजना में लाया जाएगा.
- मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80 फीसदी छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी.
- गरीबों को चार करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं. तीन करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे.
- पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, उसे लागू करेंगे.
- मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये का लोन मिलेगा.
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी.
- 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे.
- विंयांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगा.
- युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विस और टूरिज्म के जरिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे.
- एक करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, आगे तीन करोड़ को बनाएंगे.
- नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे.
- बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे. श्रीअन्न को सुपरफूड की तरह स्थापित करेंगे, नेनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे.
- मछुआरों के जीवन से जुड़े हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत करेंगे.
- मछली पालकों को सी-वीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे.
- गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, कुली, सभी को ई-श्रम से जोड़ेंगे और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे.
- तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के जरिए भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे.
- भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे.
- 2025 को जनजातीय गौरव वर्ग के रूप में घोषित करेंगे.
- एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे.
- ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे.
- ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा.

बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है. जेपी नड्डा ने दावा किया कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के हर गांव तक सड़क पहुंच गई है.

- चार करोड़ लोगों को बीजेपी सरकार की वजह से पक्के मकान मिले हैं.
- दो लाख पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा.
- 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए.
- राम लला विराजमान हुए.
- 11 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर हासिल हुआ.
- 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का फायदा मिला.
- लॉकडाउन लगाकर दो महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया.
- 10 साल से देश मान रहा है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है.
- आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम बना, दुनियाभर में इसकी चर्चा हुई.

कांग्रेस के घोषणापत्र के वादे कितने असरदार?

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है. इस दौरान पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया. घोषणा पत्र में वोटिंग के तरीके (ईवीएम) में बेहतरी की बात की गई है. पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हक़ों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी. लेकिन घोषणा पत्र में उठाए गए कई मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं. कई योजनाएं सीधे-सीधे मोदी सरकार की योजनाएं सरीखी लग रही हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार की नकल जैसे लग रही हैं. जैसे कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपये प्रति युवा देने का वादा किया है. इसी तरह की राशि मोदी सरकार भी युवाओं को रोजगार के लिए देती है.

कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला क़ानून भी लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा.

हालांकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का वादा करने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में किए गए इन वादों का कितना असर होगा.

कांग्रेस ने जिन मुद्दों को अपने घोषणापत्र में उठाया है, उनकी अहमियत समझाते हुए राजनीतिक विश्लेषक और अंग्रेजी अखबार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा कहते हैं, ''लोकतंत्र का मतलब महज़ वोट डालना नहीं है, और इसके बहुत सारे हिस्से हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है.''

केरल और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए विनोद शर्मा कहते हैं, ''दोनों प्रदेशों में राज्यपाल राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव के हालात बने रहे हैं और दूसरी सरकारें भी जीएसटी के पैसे समय पर न मिलने जैसी शिकायतें करती हैं.''

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश में मदरसों पर आए हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा क़ानून को ग़लत बताया था. लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है.

विनोद शर्मा कहते हैं कि 'वर्तमान केंद्र और कई राज्यों की सरकारें कभी नागरिकता कानून संशोधन, और 'लव जिहाद' जैसे मुद्दे लाकर लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बराबर हमले करती रहती हैं. साथ ही

वोटरों को ये जानने का अधिकार है कि उसका मत सही व्यक्ति को गया है या नहीं.'

वहीं केरल में कांग्रेस पार्टी की नेता शमा मोहम्मद का कहना था कि नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता कानून लाती है लेकिन उसमें वो श्रीलंका के तमिल हिंदुओं, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य को क्यों भूल जाती है? आख़िर इन लोगों को भी तो भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस के घोषणापत्र में जिसे 'न्याय पत्र' बताया गया है, उसमें ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही गई है ताकि वोटरों के वोटों का मिलान किया जा सके और वोटर ये जान सकें कि उनका वोट किसको गया है. चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता 'बहाल' करने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है.

मोदी सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक- चुनाव आयुक्तों की बहाली में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है.

आलोचकों का कहना है कि एक तरह से चुनाव समिति में दो व्यक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सदस्य दोनों सरकार के आदमी हैं तो सरकार का पाला नियुक्ति में भारी हो जाता है.

कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पीएम केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात कही है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश की सबसे ऊंची अदालत ने गैरकानूनी करार दिया है. इसके बाद जारी डेटा से ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने कुल कीमत और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है.

कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपये प्रति युवा देने का वादा किया है. उसने यह भी कहा है कि अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बहाली की पुरानी व्यवस्था कायम की जाएगी.

नरेंद्र मोदी सरकार की फौज में बहाली की अग्निपथ स्कीम बेहद विवादास्पद रही है. इसको लेकर फौज के पूर्व अफसर भी हैरत जताते रहे हैं.युवाओं में भी फौज में चंद सालों की भर्ती स्कीम को लेकर बेहद नाराज़गी दिखी थी हालांकि धीरे-धीरे ये शांत पड़ गई. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है कि फौज में भर्ती को दूसरे क्षेत्रों में नौकरियों की तरह नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है.

आलोक शर्मा से जब ये पूछा गया कि युवाओं को एक लाख की राशि देने की उनकी योजना क्या नरेंद्र मोदी सरकार की योजना की नकल नहीं है जो इस तरह की राशि युवाओं को रोजगार के लिए देती है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की योजना कर्ज है जिसे चुकाना पड़ता है जबकि हम युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ये राशि देंगे, और उन्हें ये पैसे वापस नहीं करने होंगे.

ग़रीब महिलाओं को एक लाख रुपये प्रति परिवार देने का वादा किया गया है.

'न्याय पत्र' को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर जारी करते समय पी चिदंबरम ने कहा कि उनकी सरकार अगर बनती है तो उसका मुख्य फोकस नौकरी, नौकरी और नौकरी रहेगा.

इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश की सबसे ऊंची अदालत ने गैरकानूनी करार दिया है. इसके बाद जारी डेटा से ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने कुल कीमत और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है.

पूर्व वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि धन के बंटवारे से पहले जरूरी है कि धन का उपार्जन हो और कांग्रेस की पिछली मनमोहन सिंह सरकार का रिकॉर्ड है कि उसने 7.5 फ़ीसद सालाना के हिसाब से आर्थिक प्रगति की थी. उस सरकार में 24 करोड़ लोग दस साल के भीतर गरीबी से बाहर निकले थे.

उन्होंने वादा किया कि अगर सरकार फिर बनती है तो इतने ही लोगों को गरीबी से बाहर लाने को वो प्रतिबद्ध होगी. कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है किसानों की कर्ज माफी का वादा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला क़ानून. अभी भी पंजाब के किसानों के कई समूह पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. 2020 में भी दिल्ली के पांच बॉर्डरों पर किसानों ने चौदह माह तक धरना दिया था.

कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी किसानों को देश में सबसे अधिक धान का मूल्य दिया था, साथ ही क़र्ज़ माफ़ी भी की थी. लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इन वादों के बावजूद कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था.

न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपये रोज़ाना करने का वायदा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है. सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पार्टी ने जातीय जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म करने की बात कही है.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस देने की बात कर रही है. आलोक शर्मा से हमने ये भी पूछा कि संविधान के मौलिक अधिकारों (आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 28, 29, 30) को लेकर उनके दल ने जो वादा किया है कहीं उसका उल्टा असर तो नहीं होगा, जिसमें एक वर्ग उनसे नाराज़ हो सकता है? तो उनका कहना था कि संविधान की रक्षा वोट की चिंता करके नहीं हो सकती है.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का हवाला देते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि 'आज समय है कि नेताओं को लोगों को सही दिशा दिखानी होगी जैसे चंद्रशेखर कहते थे कि नेता हम हैं या वो!'

कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने याद किया कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी हो रहा है, वो कांग्रेस के बड़े नेता जगजीवन राम का जन्मदिन भी है, इसलिए ये एक बड़ा दिन है. हालांकि जगजीवन राम आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी के साथ चले गए थे जिसने 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराकर दिल्ली में सरकार बनाई थी.

नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के तीन दर्जन संगठन

कांग्रेस मजबूत, लेकिन विपक्ष के बिखरने से फायदा

1996 के चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला था। तब बनवारीलाल पुरोहित सांसद चुने गए थे। 2014 में नितिन गडकरी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। तभी से वे नागपुर सीट से सांसद हैं।

महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दो बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। विकास ठाकरे नागपुर वेस्ट से विधायक हैं और मेयर रह चुके हैं।

गडकरी अपने काम गिनाकर 5 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्हें जिताने के लिए आरएसएस के 36 संगठन मैदान में हैं। इससे दीगर नागपुर में एक रेड लाइट एरिया है गंगा-जमुना। यहां रहने वाली महिलाएं अपने सांसद नितिन गडकरी से नाराज हैं। कहती हैं कि गडकरी हमारा घर तुड़वाना चाहते हैं। सरकार से कोई फायदा तो नहीं मिलता, बल्कि बचे रहें, इसलिए रिश्वत जरूर देनी पड़ती है।

गंगा जमुना एरिया में 10 हजार वोटर हैं। यहां रहने वाली महिलाओं के लिए काम कर रहीं ज्वाला धोते कहती हैं, 'हम नोटा में वोट दे देंगे, लेकिन नितिन गडकरी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने गरीब महिलाओं के घर उजाड़ने की कोशिश की है।'रेड लाइट एरिया की महिलाएं भले गडकरी से नाराज हों, लेकिन उनके काम से ज्यादातर लोग खुश हैं।

नागपुर सीट आरएसएस का मुख्यालय, कभी कांग्रेस का गढ़ था नागपुर : करीब 99 साल पहले केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया, तो हेडक्वॉर्टर के लिए अपने शहर नागपुर को चुना। आरएसएस का हेडक्वॉर्टर होने के बावजूद नागपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा। 1952 से 1996 तक और 1998 से 2009 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही।

1996 के चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला था। तब बनवारीलाल पुरोहित सांसद चुने गए थे। 2014 में नितिन गडकरी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। तभी से वे नागपुर सीट से सांसद हैं।

नागपुर का 200 साल पुराना गंगा जमुना रेड लाइट एरिया शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इतवारी इलाके में आता है। 12 एकड़ में फैले गंगा जमुना में हजारों महिलाएं परिवार के साथ रह रही हैं। पुलिस ने 2021 में यहां देह व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। रास्तों पर पहरा बिठा दिया। अब भी यहां अक्सर पुलिस की रेड पड़ती रहती है।

एक महिला कहती हैं, 'नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं। चुनाव के बाद रेडलाइट एरिया को हटाने,

तोड़ने की बात करते हैं।'

'पुलिस अक्सर यहां रेड करती है। किसी को भी पकड़कर ले जाती है। एक बार पकड़े जाने का मतलब है तीन महीने की जेल। छूटने के लिए एक लाख रुपए देने पड़ते हैं। पुलिस को इतने पैसे देंगे तो खाएंगे क्या। सरकार की किसी योजना का तो हमें फायदा नहीं मिलता।'

एक और महिला हैं, जो 30 साल से इस एरिया में रह रही हैं। कहती हैं, 'अभी चुनाव है इसलिए हमारे यहां पुलिस रेड नहीं कर रही है। अगर हम जेल चले गए तो इन नेताओं को वोट कौन देगा। डर है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, पुलिस रेड डालने लगेगी। पुलिसवाले डंडा मार-मारकर ले जाते हैं। हमारी मजबूरी हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता।'

ज्वाला धोते गंगा-जमुना में रहने वाली महिलाओं के लिए काम करती हैं। वे कहती हैं, 'ये इलाका शहर के बीचों-बीच आता है। इस पर बिल्डर लॉबी की नजर है। वे चाहते हैं कि यहां काम करने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को हटाकर, उनके घरों को तोड़कर बिल्डिंग्स बना दी जाएं।'

ज्वाला बताती हैं, '2020 में नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे अमितेश कुमार ने महिलाओं को हटाने के लिए यहां के हर रास्ते पर पुलिस बिठा दी थी। 6 महीने तक महिलाएं परेशान होती रहीं। हमने आंदोलन किया, कोर्ट गए। अदालत के आदेश पर एरिया फिर से खोला गया।' यहां गडकरी का सबसे ज्यादा विरोध है.

नागपुर में प्रवेश करते ही शानदार चौड़ी सड़कों, मेट्रो ट्रैक जैसे डेवलपमेंट पर नजर जाती है। नितिन गडकरी प्रचार के लिए जहां भी जा रहे हैं, अपने काम बता रहे हैं। हालांकि, उनके घर से 10 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर बस्ती की हालत इतनी अच्छी नहीं है।

यहां मुलाकात विमल से हुई। उनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, इसलिए टंकी से पानी लेने आई थीं। हमने पूछा- इस बार किसे वोट देंगी? विमल जवाब देती हैं, 'कोई भी आए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो नल लगाकर देगा, उसे ही वोट देंगे।'

यहीं रहने वाली रंजना वाघमारे कहती हैं, 'हमारे यहां पानी नहीं आता। नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं। हम लाइन में लगकर उन्हें वोट देते हैं। इसके बावजूद नेताओं ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया।'

यहीं मिले कैब ड्राइवर नितिन वासनिक को नितिन गडकरी का काम पसंद है। वे कहते हैं, 'नितिन गडकरी की बात ही निराली है। उन्होंने शहर में काफी डेवलपमेंट किया है, शानदार सड़कें बनाई हैं। उन जैसा काम शायद कोई और नहीं कर पाएगा। हालांकि पढ़ा-लिखा होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलनी, ये बहुत खलता है।'

विदर्भ जनजागरण समिति के अध्यक्ष नितिन रोंघे बताते हैं कि नागपुर में 10 साल में रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो और फ्लाईओवर्स बहुत बने हैं। पक्की सड़कें बनने से वाटर लॉगिंग और गर्मी बढ़ रही है। इसका मतलब कि नागपुर में बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।

दूसरी समस्या है कि नागपुर में इंडस्ट्री नहीं हैं। नेता कहते हैं कि नागपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर हब बन गया है और अब इंडस्ट्री लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हैंड इन हैंड काम करना होगा। नागपुर में करीब 7000 मेगावाट

का पावर प्लांट है। प्लांट में 2 रुपए 60 पैसे में बनने वाली एक यूनिट बिजली इंडस्ट्री को 12 रुपए में दी जाती है। फिर इंडस्ट्री यहां क्यों आएंगी, नौकरियां कैसे मिलेंगी।'

23 अप्रैल को नागपुर में एक सभा में नितिन गडकरी ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतूंगा।'

उनसे इस भरोसे की वजह पूछी। सवाल किया कि आपने ऐसा क्या किया है, जो इतनी बड़ी जीत मिलेगी। गडकरी बोले, 'क्या किया और क्या नहीं किया, ये मैं नहीं कहूंगा। आप जनता के बीच जाइए और उनसे पूछिए कि मैंने क्या किया है। इसमें कुछ मेरा विरोध करने वाले भी

2020 में नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे अमितेश कुमार ने महिलाओं को हटाने के लिए यहां के हर रास्ते पर पुलिस बिठा दी थी। 6 महीने तक महिलाएं परेशान होती रहीं। हमने आंदोलन किया, कोर्ट गए। अदालत के आदेश पर एरिया फिर से खोला गया।' यहां गडकरी का सबसे ज्यादा विरोध है.

हो सकते हैं। मैं अपना डमरू खुद नहीं बजाता और न ही मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए।

मैं जनता के बीच कहता हूं कि आपको मेरा काम उचित लगे तो ही मुझे वोट दीजिए। मुझे जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैंने उनके भी काम किए हैं। नागपुर के कई इलाकों में मुझे 1, 10 या 12 वोट मिले। वहां भी मैंने मंदिर और रोड बनवाए, दूसरे काम कराए। वहां नया फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहा हूं। 400 बेड वाला मेडिकल कॉलेज भी बनाने की मेरी इच्छा है।'

नितिन गडकरी ने कहा कि प्रचार की राजनीति से मुझे घृणा है। मैं करेज की राजनीति करता हूं। हालांकि, गडकरी भयानक गर्मी के बीच नागपुर की सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार वाहन में स्प्रिंकलर लगे हैं, जो गर्मी से बचाते हैं।

--हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ : कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे कहते हैं, 'गडकरी 2014 और 2019 में लगातार जीते हैं। नागपुर डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री का घर है। इसके बावजूद मुझे दबाव महसूस नहीं हो रहा है। कांग्रेस यहां 13 बार लोकसभा चुनाव जीती है और बीजेपी सिर्फ 3 बार। ये तो कांग्रेस का गढ़ है।'

आरएसएस नेता बोले- संघ और बीजेपी के अलावा नितिन गडकरी का पर्सनल वोट बैंक

आरएसएस से जुड़े दिलीप देवधर कहते हैं कि नितिन गडकरी नागपुर से 3 से 4 लाख वोटों से जीतते आ रहे हैं। इसके पीछे उनका 25 से 30 साल किया काम है। वे यहां 'रोड करी, पुल करी' के नाम से फेमस हैं। 2007 के बाद संघ ने नागपुर में सद्भाव गतिविधि शुरू की थी। इसके लिए गडकरी ने बहुत काम किया।

नागपुर में संघ परिवार के 36 संगठन काम कर रहे हैं। इसके लाखों कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं। गडकरी ने नागपुर में काफी काम किया है। वे यहां ऑल पार्टी कैंडिडेट की तरह चुनाव में खड़े हैं।

पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप मैत्रा कहते हैं, 'नितिन गडकरी तीसरी बार जीत रहे हैं, लेकिन 5 लाख वोट से जीतने का दावा मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट विकास ठाकरे भी मजबूत नेता हैं। वे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटिंग एमएलए हैं और पूर्व मेयर रह चुके हैं। गडकरी चुनाव जीतते भी हैं, तो अंतर एक लाख से ज्यादा नहीं रहेगा।

प्रदीप आगे कहते हैं, 'गडकरी नागपुर में किए डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लान को लेकर लोगों के बीच जा रहे है। पिछले 10 साल में यहां एम्स, आईआईटी और आइआइएम बना है। कई टॉप इंस्टीट्यूट आए। यहां मेट्रो और सड़कों पर काफी काम हुआ है। इन्हीं पर गडकरी वोट मांग रहे हैं।'

प्रदीप कहते हैं, 'महाराष्ट्र में जिस तरह से दो पार्टियां और परिवार टूटे हैं, इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। शरद पवार की लोकप्रियता 2019 जैसी नहीं बची है। विदर्भ में भले ही उद्धव वाली शिवसेना के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन वे प्रचार में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने यहां रैली नहीं की है। विपक्ष बिखरा हुआ है। वे पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। वे लोकल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे।'

छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव से पहले सुरक्षाबलों ने किया 29 नक्सलियों को ढेर

छत्तीसगढ़ में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद हो गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इनमें 2 डीआरजी के जवान हैं। मौके से पांच एके-47 बरामद की गईं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। डीआरजी का घायल जवान सूर्यवंशी श्रीमाली धमतरी जिले के नगरी का रहने वाला है। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग है। कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब साढ़े पांच घंटे तक मुठभेड़ हुई। डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने माओवादियों के ठिकाने में घुसकर उनके 29 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के वक्त नक्सली दोपहर का खाना खाकर बेफिक्र होकर बैठे थे। इनका कमांडर शंकर राव मीटिंग लेने की तैयारी कर रहा था। करीब 250 से 300 मीटर तक जवान उनके करीब पहुंच गए थे। इसके बाद मौका मिलते ही हमला कर दिया। इस मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ जवान पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं।

पहला दिन- तारीख 15 अप्रैल...पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि कांकेर के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के हापाटोला के जंगल में नक्सली मौजूद हैं। यहां नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन का कमांडर शंकर राव आया हुआ है। अपने साथियों की बैठक लेने वाला है। उनके साथ करीब 40 से 50 नक्सलियों का जमावड़ा है।

मुखबिर की इसी सटीक जानकारी के बाद डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। दूसरा दिन- 16 अप्रैल को पहाड़, नदी-नाले पार कर करीब 300 से 400 जवान नक्सलियों को घेरने उनके गढ़ में घुस गए। नक्सली जिस जंगल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानकर रुके थे, वह टेकरी वाला इलाका था। लगभग 1 से डेढ़ बजे के बीच जवान नक्सलियों के ठिकाने के नजदीक पहुंच गए थे। जवानों और नक्सलियों के बीच की दूरी महज 250 से 300 मीटर ही थी।

पेड़ और मेड़ का सहारा लेकर जवान छुप गए। जहां नक्सली मौजूद थे, उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। यहां नक्सली कमांडर शंकर अपने साथियों के साथ खाना खाकर निश्चित बैठा था। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर से कुछ देर पहले शंकर अपने साथियों के साथ मीटिंग करने वाला था। इसके पहले ही ठीक 2 बजे पुलिस ने फायर खोल दिया।

समय 3 बजकर 30 मिनट- शुरुआती फायरिंग में ही 2 से 3 नक्सली मारे गए। बाकी जब तक संभलते, तब तक जवानों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। 3 से 3:30 बजे तक जवानों ने 8 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए थे। इसके बाद और गोलीबारी हुई। समय शाम 7 बजकर 30 मिनट- करीब साढ़े 5 घंटे तक मुठभेड़ चली। फायरिंग रुकी तो जवानों ने मुठभेड़ वाले इलाके की सर्चिंग की। फोर्स ने पहले 18 और फिर बाद में 11 और, इस तरह कुल 29 नक्सलियों के शव बरामद किए। इस मुठभेड़ में जवानों ने 8-8 लाख के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव और ललिता को ढेर कर दिया। कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, जो मौके से भाग निकले।

मूंछ पर ताव देकर जवान बोला- हमने बहादुरी से नक्सलवाद को जल्द खत्म कर देंगे- अमित शाह : गृहमंत्री अमित शाह के मुताबिक मोदी सरकार के नेतृत्व और छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही 3 महीने में 80 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं। वहीं 150 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया है।

एके-47 और इंसास राइफल रखते थे दोनों नक्सली लीडर : ललिता और शंकर उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी में नक्सलियों के डीवीसीएम पद पर एक्टिव थे। ललिता की उम्र करीब 50 साल थी। ये अपने पास इंसास राइफल रखती थी। वहीं, शंकर की उम्र करीब 47 साल थी। वह अपने पास एके-47 रखता था।

दक्षिण इलाके में फोर्स आक्रामक, अब उत्तर की तरफ नक्सलियों का रुख : छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर संभाग है। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस फोर्स आक्रामक हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले करीब तीन महीने में जवानों ने 79 नक्सलियों को मार गिराया है।

कई बार पुलिस से बचकर निकल चुका था शंकर राव : इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, कांकेर इलाके में नक्सली कमांडर शंकर का जबरदस्त असर था। उस इलाके में जितनी भी नक्सल घटनाएं हुई हैं, ज्यादातर का मास्टरमाइंड यही था। कई बार मुठभेड़ में ये पुलिस की गोलियों से बच निकला था, लेकिन 16 अप्रैल की मुठभेड़ में मारा गया।

मुकाबला किया : इस मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि तीनों की हालत खतरे से बाहर है। देर शाम छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा जवानों से मिलने पहुंचे। तब बेड पर लेटे एक जवान ने अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा- सर हम मरने से नहीं डरते, पूरी बहादुरी से लड़े हैं। 29 को मार गिराया है।

यह इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ऐसे में नक्सली बार-बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। जिससे अलग-अलग जिलों की पुलिस के रडार पर आ रहे हैं। उन्हें मारने में जवानों को कामयाबी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दक्षिण में जवानों के आक्रामक होने की वजह से अब नक्सलियों का रुख उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ है। कुछ नक्सली अपना एरिया छोड़कर जा भी चुके हैं।

पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान सम्पन्न हो गया।

उत्तर प्रदेश की आठ, उत्तराखंड की पांच और पश्चिम बंगाल की तीन लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की दो और असम की पांच लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। बिहार की चार, छत्तीसगढ़ की एक, मध्य प्रदेश की छह, महाराष्ट्र की पांच और मणिपुर की दो लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई। मेघालय की दो, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की एक-एक सीट पर पहले चरण में वोट डाले गये।

पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम एक राज्यपाल की किस्मत है दांव पर

लोकसभा चुनाव 2024 : पहला चरण

राज्य : 21

सीटें : 21

सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत

पहले चरण में चुनाव, वहां 2019 में ऐसा था मतदान

69.96%

सबसे ज्यादा
87.03%
अरुणाचल पूर्व

सबसे कम
49.73%
नवादा (बिहार)

देश के 21 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण सम्पन्न हुआ जिसके तहत 102 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस चरण में चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने की आस लगाये बैठे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनाव मैदान में थे।

अरुणाचल और असम के उम्मीदवार : अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट पर रीजीजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई के वर्तमान अध्यक्ष नबाम तुकी से है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट कटने के बाद राज्यसभा सदस्य सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा गया है।

मुजफ्फरनगर और उधमपुर : यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मुकाबला समाजवादी पार्टी (सपा) के हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार दारा सिंह प्रजापति से है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल और दो बार के सांसद जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। यादव का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक ललित यादव से है।

अलवर और तमिलनाडु : अलवर सीट से मौजूदा सांसद बालक नाथ का टिकट कट गया है। राजस्थान की बीकानेर संसदीय सीट पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद

21 राज्यों की102 सीटों पर 68% वोटिंग

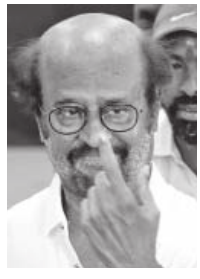

राम मेघवाल से है। तो वहीं, तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट पर द्रमुक सांसद एवं पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा का मुकाबला भाजपा के एल मुरुगन से है जो केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए मुरुगन पहली बार नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

शिवगंगा कोयंबटूर : शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम कांग्रेस के टिकट पर पुनः मैदान में हैं और उनका मुकाबला भाजपा के टी देवनाथन यादव और अन्नाद्रमुक के जेवियर दास से है। कार्ति के पिता, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शिवगंगा लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने गए थे। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के.अन्नामलाई कोयंबटूर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता गणपति पी.राजकुमार और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के सिंगाई रामचंद्रन से है।

हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिलिसाई सौंदरराजन सक्रिय राजनीति में वापसी करते हुए चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी अनंत की बेटी तमिलिसाई सौंदरराजन ने तूतुकोड़ी लोकसभा सीट से द्रमुक नेता कनिमोई के खिलाफ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थीं।

छिंदवाड़ा और त्रिपुरा : कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जिन्होंने 1980 के बाद से नौ बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 29 में से 28 सीट जीती थीं लेकिन छिंदवाड़ा पर विजय प्राप्त करने से चूक गई थी। पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा के बीच मुकाबला है। मणिपुर के कानून एवं शिक्षा मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार बसंत कुमार सिंह इनर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर व कांग्रेस उम्मीदवार बिमल अकोइजाम से है।

राजस्थान : भाजपा का गढ़ मानी जानी वाली उत्तरी राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट पर दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी और भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वां से है। कस्वां ने टिकट मिलने पर अप्रैल में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। देश की 18 वीं लोकसभा के लिए सात चरणों में 543 सीट पर मतदान होगा और मतगणना चार जून को होगी।

26 को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान

पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। केरल में सबसे अधिक 500 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि नाम वापसी के बाद यहां की 20 सीटों पर कुल 194 प्रत्याशी मैदान में हैं। कर्नाटक में 491 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 92 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था।

दूसरे चरण में इन राज्यों में होगा मतदान

राज्य	सीटों की संख्या
असम	05
बिहार	05
छत्तीसगढ़	03
जम्मू एवं कश्मीर	01
कर्नाटक	14
केरल	20
मध्य प्रदेश	06
महाराष्ट्र	08
राजस्थान	13
त्रिपुरा	01
उत्तर प्रदेश	08
पश्चिम बंगाल	03

बाह्य मणिपुर लोकसभा सीट की 15 विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था। इस निर्वाचन क्षेत्र की 13 विधान सभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में भी मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना था। मगर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद अब चुनाव सात मई को तीसरे चरण में होगा।

दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटें: वायनाड में राहुल गांधी की अग्निपरीक्षा, 3 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर, लोकसभा अध्यक्ष भी मैदान में

दूसरे चरण में दो पूर्व मुख्यमंत्री और तीन केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के भाग्य का फैसला भी जनता 26 अप्रैल को करेगी। वायनाड से राहुल गांधी दूसरी बार और कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार मैदान में हैं। हेमा मालिनी की मथुरा सीट और मेरठ से चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल पर सबकी निगाहें हैं।

पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 24 अप्रैल की शाम से प्रचार अभियान

थम जाएगा। 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर हैं।... आइए जानते हैं वे हाई-प्रोफाइल सीटें जिन पर होंगी पूरे देश की निगाहें।

वायनाड लोकसभा सीट : दूसरे चरण में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन्हीं में से एक सीट है वायनाड। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 4,31,770 मतों से चुनाव जीता था। राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने महिला प्रत्याशी एनी राजा को उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से पीआर कृष्णनकुट्टी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ के. सुरेंद्रन पर भरोसा जताया है। वायनाड में पांच निर्दलीय समेत कुल नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

राजनांदगांव लोकसभा सीट : छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट दूसरे चरण की हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दुर्ग के रहने वाले बघेल की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। भूपेश के सामने भाजपा के संतोष पांडेय हैं। बसपा ने यहां देवलाल सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सात निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं।

मान्डया लोकसभा सीट : कर्नाटक की मान्ड्या लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की साख दांव पर है। कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल (सेक्युलर) का लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हैं। कांग्रेस ने उनके सामने वेंकटरमण गौड़ा को उतारा है। इस सीट पर सात निर्दलीय समेत कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं।

तिरुअनंतपुरम लोकसभा सीट: केरल की तिरुअनंतपुरम सीट की चर्चा भी पूरे देश में है। यहां से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से उनका मुकाबला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पन्न्यन रविंद्रन को टिकट दिया है। बसपा से एडवोकेट राजेंद्रन भी चुनावी समर में उतरे हैं। सात निर्दलीय समेत कुल 12 प्रत्याशी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

जोधपुर लोकसभा सीट : 26 अप्रैल को राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं। बसपा से मंजू मेघवाल और कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा की चुनौती शेखावत के सामने है। जोधपुर सीट पर छह निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं।

कोटा लोकसभा सीट : राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। बसपा से धनराज यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर नौ निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट : उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें इस वजह से हैं कि यहां से केंद्रीय मंत्री रहे डॉ. महेश शर्मा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) ने डॉ. महेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया है। बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी प्रत्याशी हैं। यहां से चार निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं।

अट्टिंगल लोकसभा सीट: केरल की अट्टिंगल लोकसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस ने उनके सामने अडूर प्रकाश को अपना प्रत्याशी बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से एडवोकेट वी जॉय और बसपा से एडवोकेट सुरभि एस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीन निर्दलीय समेत कुल सात प्रत्याशी इस सीट पर उतरे हैं।

झालावाड़-बारा लोकसभा सीट: राजस्थान की झालावाड़-बारा लोकसभा सीट को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। 2009 से अब तक यहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। दुष्यंत सिंह चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उर्मिला जैन और बसपा ने चंद्र सिंह किराड़ को उतारा है। तीन निर्दलीय समेत कुल सात प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ रहे हैं।

जालोर लोकसभा सीट: राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव के सामने भाजपा ने लुंबाराम को उतारा है। छह निर्दलीय समेत 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

मथुरा लोकसभा सीट: उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। वजह फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं। भाजपा ने मथुरा सीट से हेमा मालिनी को तीसरी बार उतारा है। वे दो बार यहां से जीत भी दर्ज कर चुकी हैं। हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस के मुकेश धनगर और बसपा के सुरेश सिंह की चुनौती है। मथुरा सीट पर 10 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

मेरठ लोकसभा सीट: रामायण के 'राम' अरुण गोविल उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट पर अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने सपा ने सुनीता वर्मा और बसपा ने देवव्रत कुमार त्यागी को उतारा है। यहां से कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

मैसूर लोकसभा सीट : कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व राजपरिवार के सदस्य पर भरोसा जताया है। भाजपा की टिकट पर यादुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने अपने राज्य प्रवक्ता एम, लक्ष्मण को उतारा है। इस सीट पर आठ निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी मैदान में हैं।

बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट : भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या की साख बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट पर दांव पर है। तेजस्वी ने पिछला चुनाव यहां से जीता था। कांग्रेस ने यहां सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है। इस सीट पर 12 निर्दलीय समेत कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं।

पूर्णिया लोकसभा सीट : इस चुनाव में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट शुरुआत से ही चर्चा में रही है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने यहां बीमा भारती को उतारा है। कांग्रेस की टिकट पर पप्पू यादव चुना लड़ना चाहते हैं लेकिन राजद से बात नहीं बनी। अब इसी सीट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय उतरे हैं। बसपा से अरुण दास मैदान में हैं। यहां कुल सात प्रत्याशी चुनाव में हैं।

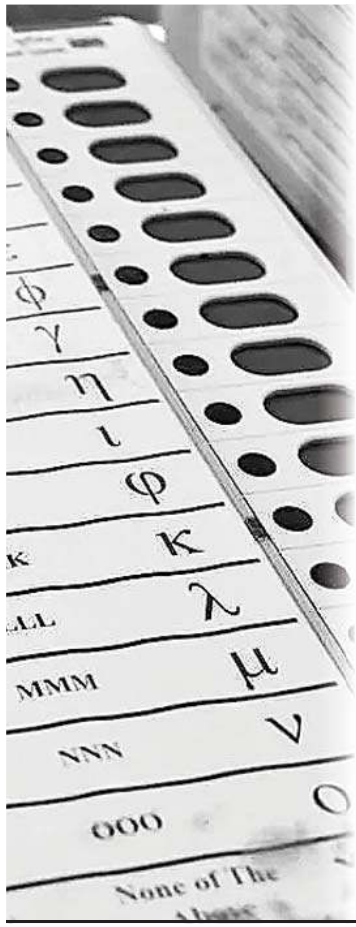

इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान

- **असमः** दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
- **बिहारः** किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
- **छत्तीसगढ़ः** राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
- **जम्मू-कश्मीरः** जम्मू लोकसभा ।
- **कर्नाटकः** उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
- **केरलः** कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
- **मध्य प्रदेशः** टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
- **महाराष्ट्रः** बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल-वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
- **राजस्थानः** टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और झालावाड़-बारा।
- **त्रिपुराः** त्रिपुरा पूर्व।
- **उत्तर प्रदेशः** अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद और मथुरा।
- **पश्चिम बंगालः** दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।

डीवीसी का पिछले वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन

डीवीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में 44314.6 एमयू बिजली उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया। 75 साल के इतिहास में उच्चतम संचयी उत्पादन हासिल किया है, जिसमें 44125.5 एमयू थर्मल, 180 एमयू हाइडल और 9.1 एमयू सौर ऊर्जा शामिल है।

डीवीसी ने वित्त वर्ष 23-24 में 76.81% पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) पर उच्चतम थर्मल उत्पादन हासिल किया, जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक है और 68% के राष्ट्रीय पीएलएफ से काफी आगे है। वित्त वर्ष 2023-24 में डीवीसी के अधिकांश प्लांट 80% से अधिक पीएलएफ पर चले हैं। डीवीसी ने इस वर्ष भेजे गए 346 कोयला रैक के साथ तुबेद, लातेहार में अपनी कैप्टिव कोयला खदानों से वित्त वर्ष 2023-24 में 1.52 एमएमटी कोयला उत्पादन हासिल किया है। डीवीसी ने कोयले के साथ बायोमास छर्रों की सह-फायरिंग के माध्यम से बिजली पैदा करना शुरू कर दिया।

एस सुरेश कुमार
डीवीसी, अध्यक्ष

डीवीसी ने अपने विभिन्न संयंत्रों में फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली स्थापित की।Ø कोयला आधारित थर्मल संयंत्रों से उत्पन्न 108.26% राख का उपयोग किया। वित्त वर्ष 23-24 में डीवीसी के बिजली बिक्री राजस्व के बिलिंग और संचयी संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में क्रमशः 3.12% और 9.5% (अनंतिम) की वृद्धि प्राप्त की है। 2023 में डीवीसी ने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए।

एमसीएल 200 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बनी

संबलपुर। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने 200 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन कर इतिहास रच दिया है। एमसीएल कोल इंडिया (सीआईएल) की पहली अनुषांगिक कंपनी है, जो 200 मिलियन टन के आंकड़े पर पहुंची है। इधर, कोल इंडिया लिमिटेड (का 23 अप्रैल की स्थिति में कुल उत्पादन 749.67 मिलियन टन पर पहुंच गया है।

कंपनी ने 23 अप्रैल, 2024 की स्थिति में 200.39 मिलियन टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी के समक्ष 204 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 193.3 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया गया था।

इधर, कोल इंडिया लिमिटेड का 23 अप्रैल की स्थिति में कुल उत्पादन 749.67 मिलियन टन पर पहुंच गया है। सीआईएल के समक्ष 780.20 मिलियन टन का टारगेट है।

चुनाव में प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक लें : प्रशांत किशोर

> दुनियाभर के अच्छे और बड़े नेताओं की एक विशेषता है। वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं

2024 आसन्न लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार (पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट) प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में यह बात कही।

प्रशांत ने कहा- राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद वे न तो राजनीति से अलग हुए और न ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दिया। मेरी नजर में यह लोकतांत्रिक नहीं है।

प्रशांत ने कहा- जब आप (राहुल गांधी) पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है, तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को पांच साल के लिए करने देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा ही किया था।

प्रशांत ने कहा- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया। 1991 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी। उसका परिणाम आप सबको पता है।

हिंदी पट्टी में नहीं जीते, तो वायनाड जीतने का फायदा नहीं : प्रशांत ने राहुल को लेकर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीते, तो वायनाड से जीतने का कोई फायदा नहीं है। अकेले केरल जीतकर आप देश नहीं जीत सकते। अमेठी छोड़ देने से भी गलत संदेश जाएगा।

प्रशांत ने प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए कहा- नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने गृह राज्य गुजरात के साथ-साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था। इसलिए, क्योंकि आप भारत को तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतते या हिंदी पट्टी में मौजूदगी दर्ज नहीं कराते।

***राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं :** प्रशांत किशोर ने कहा- दुनियाभर के अच्छे और बड़े नेताओं की एक विशेषता है। वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा- अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानते हैं, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे पूरा कर सके। यह संभव नहीं है।

राहुल ने 2019 में पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा, जो बोला किया नहीं : प्रशांत किशोर ने कहा- 2019 के चुनावों में पार्टी की हार के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। उन्होंने तब लिखा था कि वह पीछे हट जाएंगे और किसी और को पार्टी की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने जो लिखा, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके समर्थक किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़े हैं। राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए कि बार-बार विफलताओं के बावजूद वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

हार के लिए चुनाव आयोग और मीडिया पर सवाल उठाना गलत : प्रशांत ने राहुल के उन दावों पर सवाल उठाया जिसमें चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी जब वह सत्ता में थी और भाजपा का विभिन्न संस्थानों पर बहुत कम प्रभाव था।

भाजपा की जीत की वजह विपक्ष की कमजोर रणनीति : प्रशांत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नंबर एक पार्टी बनने जा रही है। तेलंगाना में भाजपा पहले या दूसरे नंबर पर रह सकती है। तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर दोहरे अंक तक पहुंच सकता है।

कुल 543 लोकसभा सीटों में से तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल में 204 सीटें हैं। हालांकि भाजपा 2014 या 2019 में इन सभी राज्यों को मिलाकर 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी।

प्रशांत ने कहा- विपक्ष की सुस्त और कमजोर रणनीति की वजह से भाजपा को दक्षिण और पूर्वी भारत

में फायदा होता दिख रहा है। इन दो क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले पार्टीके वोट शेयर और सीटें बढ़ सकती हैं। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पार्टी की पकड़ कमजोर है।

विपक्ष ने भाजपा को रोकने के मौके गंवाए : किशोर ने कहा कि भाजपा का प्रभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता है। विपक्ष के पास भाजपा के रथ को रोकने की तीन संभावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने सुस्त और गलत रणनीतियों के कारण तीनों मौके गंवा दिए।

प्रशांत किशोर ने बताया कि 2014 के बाद भाजपा बैकफुट पर थी। तब कांग्रेस इसका फायदा उठाने में विफल रही। 2015 और 2016 में भाजपा के लिए चुनावी दौर काफी निराशाजनक रहा, जब वह असम को छोड़कर कई विधानसभा चुनाव हार गई थी।

2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा का प्रदर्शन फिर से खराब रहा। 2018 में पार्टी कई राज्यों में हार गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने उसे वापस आने का मौका दिया।

2020 में कोविड के बाद मोदी को अपनी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट का सामना करना पड़ा। भाजपा पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हार गई। दूसरी तरफ, विपक्ष के नेता चुनौती का सामना करने के बजाय अपने घरों में बैठ गए, जिससे मोदी को राजनीतिक वापसी करने का मौका मिल गया। अगर आप कैच छोड़ते रहेंगे तो बल्लेबाज शतक बनाएगा, खासकर जब वह अच्छा बल्लेबाज हो।

इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पास कोई चेहरा-एजेंडा नहीं : प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा कि भाजपा को हराने के लिए अलायंस की न तो जरूरत है और न ही यह असरदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 350 सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई है।

भाजपा लगातार इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। उनके पास कोई नैरेटिव, चेहरा या एजेंडा नहीं है।

आंध्र में सीएम जगन मोहन का सत्ता में वापस आना बहुत मुश्किल : प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा- इस बार मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा। रेड्डी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय वोटर्स को खुश करने में लगे हैं।

किशोर ने कहा कि रेड्डी पुराने राजाओं की तरह हैं, जो गरीब लोगों को पैसे बांटते थे। इसी तरह रेड्डी लोगों को कैश ट्रांसफर करते हैं। उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने राज्य के लोगों को नौकरियां देने या रुके हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया है।

टाटा के पास जा रही हैं भारत में आईफोन की सभी फैक्ट्रियां

आईफोन बनाने वाली कंपनी पेगाट्रॉन तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री का नियंत्रण टाटा समूह के हाथ में दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इस समझौते से सहमत है और टाटा और पेगाट्रॉन के बीच इसे लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है.

चेन्नई के पास स्थित यह फैक्ट्री भारत में ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन की इकलौती फैक्ट्री है जहां आईफोन बनाए जाते हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि टाटा और पेगाट्रॉन के बीच चल रही बातचीत के मुताबिक इस फैक्ट्री को चलाने के लिए दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर बना सकती हैं.

रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से बताया कि टाटा समूह की योजना है कि उसकी इसमें कम से कम 65 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। पेगाट्रॉन के पास बाकी हिस्सेदारी रहेगी और साथ ही वह तकनीकी सपोर्ट भी देगी। रॉयटर्स के दो सूत्रों में से एक के मुताबिक टाटा इस फैक्ट्री को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के जरिए चलाएगी.

टाटा का फायदा : इस फैक्ट्री में करीब 10,000 कर्मचारी काम करते हैं और यहां हर साल 50 लाख आईफोन बनते हैं। पेगाट्रॉन कुछ समय से एप्पल के साथ अपनी साझेदारी को समेट रहा है। पिछले साल कंपनी ने चीन में एक आईफोन फैक्ट्री का नियंत्रण अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी लक्सशेयर को 29 करोड़ डॉलर में दे दिया था। तमिलनाडु वाली फैक्ट्री उसके नियंत्रण वाली आखिरी ऐसी फैक्ट्री है.

रॉयटर्स ने टाटा और पेगाट्रॉन को टिप्पणी के लिए ईमेल भेजी थीं लेकिन दोनों कंपनियों ने जवाब नहीं दिया। एप्पल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। रॉयटर्स के सूत्रों ने इस समझौते के लिए चल रही बातचीत की वित्तीय जानकारी साझा नहीं की.

> चेन्नई के पास स्थित यह फैक्ट्री भारत में ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन की इकलौती फैक्ट्री है जहां आईफोन बनाए जाते हैं।

चीन और अमेरिका के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में एप्पल भी अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर स्थापित करने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन टाटा को इस समझौते का फायदा मिलेगा। चेन्नई वाली फैक्ट्री आईफोन उत्पादन की उसकी योजनाओं को और मजबूत करेगी.

टाटा समूह पहले से कर्नाटक में एक आईफोन असेम्ब्ली फैक्ट्री चलाता है, जिसे उसने पिछले साल ताइवान की ही एक और कंपनी विस्ट्रॉन से लिया था। टाटा एक और फैक्ट्री तमिलनाडु के होसुर में भी बना रहा है। संभव है कि इस फैक्ट्री में पेगाट्रॉन उसका जॉइंट वेंचर साझेदार हो.

बदल रही एप्पल की रणनीति : पेगाट्रॉन भी अपने चेन्नई परिसर में पिछले कई महीनों से एक और आईफोन फैक्ट्री बना रही है। रॉयटर्स के सूत्रों में से एक ने बताया कि टाटा वाले समझौते के तहत टाटा समूह इस फैक्ट्री पर भी नियंत्रण ले सकता है। उम्मीद है कि दोनों कंपनियों के बीच बातचीत छह महीनों में पूरी हो जाएगी। पेगाट्रॉन इंडिया के सभी कर्मचारी जॉइंट वेंचर के कर्मचारी बन जाएंगे.

भारत में आईफोन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट उत्पादकों में टाटा, पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन शामिल हैं। टाटा एप्पल की भारत में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। समीक्षकों का अनुमान है कि इस साल आईफोन के कुल ऑर्डरों में से भारत से 20-25 प्रतिशत योगदान रहेगा। पिछले साल यह योगदान 12 से 14 प्रतिशत था.

पेगाट्रॉन एप्पल के व्यापार में से धीरे धीरे क्यों बाहर निकल रहा है इसके कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। पिछले साल पेगाट्रॉन ने कहा था कि चीन वाली फैक्ट्री का समझौता कंपनी के "व्यापार को ऑप्टिमाइज" करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किया गया था.

अदालत के फैसले से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी मुश्किलें बढ़ीं

▪ प्रभाकर मणि तिवारी

कलकत्ता हाईकोर्ट के दो ताजा फैसलों ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आए इन फैसलों से विपक्षी दल बीजेपी को एक मजबूत हथियार मिल गया है.

इनमें सबसे बड़ा फैसला है हाल के महीनों में सुर्खियों में रहे संदेशखाली की घटना की सीबीआई जांच का आदेश. इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खिलाफ दायर एफआईआर मामले में अदालत ने पुलिस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत के फैसले के बाद पहले से ही संदेशखाली की घटना पर आक्रामक रवैया अपनाने वाली बीजेपी का रुख और हमलावर हो गया है. बंगाल में अपनी चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों को चुन-चुन कर गिरफ्तार किया जाएगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही चेतावनी दी थी.

संदेशखाली पर कोर्ट का फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने संदेशखाली मामले पर दायर पांच जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में सीबीआई को इस घटना की जांच का निर्देश दिया. खंडपीठ ने जांच एजेंसी से एक अलग ईमेल आईडी बनाने को कहा है ताकि लोग उसके जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. साथ ही सीबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि वह पूछताछ के लिए किसी को भी बुला सकती है चाहे वह कितना ही बड़ा नेता या अधिकारी क्यों नहीं हो.

खंडपीठ का कहना था कि न्याय के हित में संदेशखाली की घटना की तटस्थ जांच जरूरी है. तमाम संबंधित पक्ष 15 दिनों के भीतर ईमेल के जरिए सीबीआई के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ईमेल के जरिए शिकायत का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रहे. कोर्ट ने सीबीआई को दो मई को होने वाले अगली सुनवाई से पहले इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

सीबीआई की यह जांच अदालत की निगरानी में होगी. खंडपीठ ने संदेशखाली में राज्य सरकार के खर्च पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लाइटें लगाने का भी निर्देश दिया है. वैसे तो अदालत ने बीते बृहस्पतिवार को ही इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी. लेकिन उसने फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई

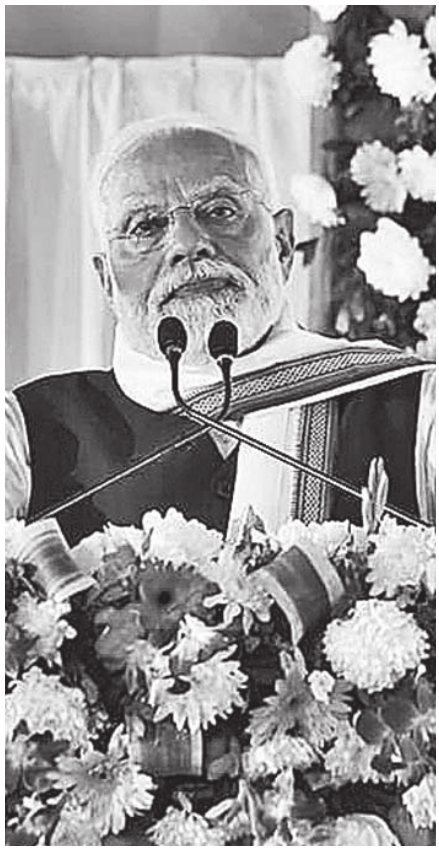

के दौरान न्यायाधीश की टिप्पणी थी कि अगर इन घटनाओं में से एक प्रतिशत भी सही है तो यह बेहद शर्म की बात है. जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए.

क्या है संदेशखाली मामला

कोलकाता से करीब 120 किमी दूर उत्तर 24-परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा पर बसा संदेशखाली इस साल जनवरी से ही सुर्खियों में है. राज्य में कथित राशन घोटाले की जांच के लिए मौके पर पहुंची ईडी की टीम पर स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला कर दिया था. उसमें ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे.

उसके बाद फरवरी में इलाके की तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर आई. उन्होंने शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और खेती की जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप लगाए थे. उसी समय तमाम राजनीतिक दलों और केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा किया और कई सप्ताह तक इलाके में धारा 144 लागू रही. दबाव बढ़ते देख कर टीएमसी ने शाहजहां समेत तीन नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया. बाद में उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस इलाके में अपनी चुनावी रैली में पीड़िताओं से मुलाकात की. पार्टी ने बशीरहाट संसदीय सीट, जिसके तहत संदेशखाली इलाका है, में एक पीड़िता रेखा पात्रा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर, इस मामले पर विवाद बढ़ते देख कर टीएमसी ने बशीरहाट में पिछली बार जीतने वाली अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट काट कर पूर्व सांसद हाजी नुरुल इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि विवाद थमने की बजाय लगातार तेज हो रहा है.

केंद्रीय एजेंसियों पर हमला

बम विस्फोट की घटना की जांच के लिए पूर्व

मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर पहुंची एनआईए की एक टीम पर भी हमला किया गया जिसमें एक अधिकारी घायल हो गए. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए इस घटना का समर्थन किया कि एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस-प्रशासन को सूचना दिए बिना ही गांव में पहुंच गई.

इस घटना पर विवाद बढ़ते ही गांव की एक महिला ने एनआईए अधिकारियों को खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को पूछताछ का समन भेज दिया. इसी के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में अपील की थी. उसकी अपील पर अदालत ने पुलिस को फिलहाल किसी भी एनआईए अधिकारी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के जज जय सेनगुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस को पूछताछ से 72 घंटे पहले नोटिस देनी होगी और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी.

पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर आने वाले बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता लगातार इन दोनों मुद्दों को उठा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बालूरघाट की रैली में कहा कि संदेशखाली में लंबे समय से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसी शर्मनाक घटना पर राजनीति करते हुए दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आधा दर्जन चुनावी रैलियां कर चुके हैं और अपनी लगभग हर रैली में वो संदेशखाली का मुद्दा उठाते रहे हैं.

----राजनीतिक दलों की खींचतान

राज्य में चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों की कथित सक्रियता टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह हमले केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल के आरोपों का नतीजा है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं. इससे राज्य के आम लोगों में धीरे-धीरे यह भावना घर कर गई है कि ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी तमाम एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही हैं.

अब अदालत की ओर से लगे ताजा झटकों के बाद टीएमसी ने कहा है कि किसी खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया गया है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि पूर्व जज और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की छाया अब भी अदालत पर नजर आ रही है. अभिजीत गांगुली ने शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकार और टीएमसी के खिलाफ एक के बाद एक कई कड़े फैसले दिए थे. उनके फैसलों के कारण ही पार्टी के कई मंत्री, विधायक और नेता जेल में हैं. बाद में वो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए और पूर्व मेदिनीपुर जिले की तमलुक सीट से मैदान में हैं. कुणाल घोष ने अदालत के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संदेशखाली मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में बढ़ रही थी. ऐसे में इसे सीबीआई को सौंपने का कोई तुक नहीं है.

मूल्यों की स्थापना के स्वर कहीं भी सुनाई नहीं दे रहे!

लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां उग्र से उग्रतर होती जा रही है, पहली बार भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बन रहा है, कुछ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाले दल अपने घोषणा पत्रों में उनके कल्याण की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का सशक्तिकरण करने की बजाय उनके तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ दल देश-विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ दल विकास योजनाओं की छिछालेदार कर रहे हैं। किसी भी दल के चुनावी मुद्दे में पर्यावरण विकास की बात नहीं हैं। व्यक्ति नहीं, मूल्यों की स्थापना के स्वर कहीं भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। सत्ता और स्वार्थ ने अपनी आकांक्षी योजनाओं को पूर्णता देने में नैतिक कायरता दिखाई है। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात करके नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों के आन्दोलन से सरकार बनाने के सच को ही बदनुमा बना दिया है। इसकी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठ गया कि चौराहे पर खड़े आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा-सा लगता है। आंखें उस चेहरे पर सचाई की साक्षी ढूंढती हैं। समस्याओं से लड़ने के लिये हमारी तैयारी पूरे मन से होनी चाहिए।

लोकतंत्र के महापर्व पर समझना चाहिए कि हमने जीने का सही अर्थ ही खो दिया है। यद्यपि बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है। कितने ही नए रास्ते बने हैं। फिर भी किन्हीं दृष्टियों से हम भटक रहे हैं। भौतिक समृद्धि बटोरकर भी न जाने कितनी रिक्तताओं की पीड़ा सही है। गरीब अभाव से तड़पा है, अमीर अतृप्ति से। कहीं अतिभाव, कहीं अभाव। जीवन-वैषम्य कहां बांट पाया अपनों के बीच अपनापन। अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं, बस्तियां बस रही हैं मगर आदमी उजड़ता जा रहा है। पूरे देश में मानवीय मूल्यों का ह्रास, राजनीति अपराध, भ्रष्टाचार, कालेधन की गर्मी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, अन्याय, शोषण, संग्रह, झूठ, चोरी जैसे-अनैतिक अपराध पनपे हैं। धर्म, जाति, राजनीति-सत्ता और प्रांत के नाम पर नए संदर्भों में समस्याओं ने पंख फैलाये हैं। हर बार के चुनावों की तरह इस बार भी आप, हम सभी अपने आपको जीवन से जुड़ी अंतहीन समस्याओं के कटघरे में खड़ा पा रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि जनता की अदालत में कहां, कौन दोषी है? पर यह चिंतनीय प्रश्न अवश्य है हम इतने उदासीन एवं लापरवाह कैसे हो गये कि राजनीति को इतना आपराधिक होने दिया? जब आपके द्वार की सीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ौसी की छत पर गन्दगी का उलाहना मत दीजिए। कोई भी अच्छी शुरूआत सबसे पहले स्वयं की की जानी जरूरी है।

देश के लोकतंत्र को हांकने वाले लोग इतने बदहवास होकर निर्लज्जतापूर्ण कारनामे करेंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौराहे पर खड़ा आदमी सब कुछ देख रहा है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि वह कौन सी राह पकड़े। आम आदमी सरकार ने शराब-शिक्षा में घोटाले किए, दागी चिन्हित भी हुए लेकिन आप सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड अपना लिए। अपनों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं, राबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ नजर नहीं आता और वे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बात केवल कांग्रेस की ही नहीं है, बात राजनीतिक आदर्शों की हैं। जिसकी वकालत करते हुए कभी अन्ना हजारे तो कभी बाबा रामदेव, कभी केजरीवाल तो कभी श्री रविशंकरजी जन-आन्दोलन की अगवाई करते देते थे, अब ना तो ऐसे आन्दोलन होते हैं न ही उन पर विश्वास रहा। हमारे भीतर नीति और निष्ठा के साथ गहरी जागृति की जरूरत है। नीतियां सिर्फ शब्दों में हो और निष्ठा पर संदेह की परतें पड़ने लगें तो भला उपलब्धियों का आंकड़ा वजनदार कैसे होगा? बिना जागती आंखों के सुरक्षा की साक्षी भी कैसी! एक वफादार चौकीदार अच्छा

कई राजनीतिक दल तो पारिवारिक उत्थान और उन्नयन के लिये व्यावसायिक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक एकता की बात कौन करता है। आज देश में भारतीय कोई नहीं नजर आ रहा क्योंकि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिल की पहचान भारतीयता पर हावी हो चुकी है।

सपना देखने पर भी इसलिए मालिक द्वारा तत्काल हटा दिया जाता है कि पहरेदारी में सपनों का खयाल चोरी को खुला आमंत्रण है।

भाजपा जो हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करती रही, उसकी शुचिता कहां है? कितने दागी एवं अपराधी नेताओं को उसने अपने दल में जगह ही नहीं दी, टिकट तक दे दिया। हो सकता है 400 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिये भाजपा की कुछ मजबूरियां हो। कमल तो खिलेगा ही, लेकिन उस खिलाहट में मजबूरियों के नाम पर मूल्यों के साथ समझौता नहीं होता तो यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का एक अनूठा उदाहरण होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कभी कहा था कि व्यक्ति को अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचाना जाना चाहिए, यह वाक्य उनके पोते राहुल गांधी पर भी लागू हो रहा है। वे तमाम सुखों एवं सुविधाओं में पले-बढ़े और उन्होंने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया या ये कहें कि जीवन के लिए संघर्ष करने की उनके सामने कोई नौबत नहीं आई। कहते हैं - "जा के पैर न परी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई"। जब आप लोगों की पीड़ा को उसी भाव से महसूस नहीं कर पाते तो दूसरों को आपकी बात पर भरोसा नहीं हो पाता। इस भरोसे को पाने के लिए उस पीड़ा को पहले खुद भुगतना होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी सच्ची और ठीक बात कहते हैं तब भी लोग उसे उस सच्चाई के साथ, उस भाव में अंगीकार नहीं कर पाते। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मौजूदा यह आचरण स्वीकार्य नहीं। पूरा राजनीतिक वातावरण ही हास्यास्पद हो चुका है। यदि हालात नहीं सुधरे तो राजनीतिक दलों की दुर्गति तय है। बदलती राजनीतिक सोच एवं व्यवस्था के मंच पर बिखरते मानवीय मूल्यों के बीच अपने आदर्शों को, उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, परम्पराओं को और जीवनशैली को हम कोई ऐसा रंग न दे दें कि उससे उभरने वाली आकृतियां हमारी भावी पीढ़ी को सही रास्ता न दिखा सकें।

राजनीति का वह युग बीत चुका जब राजनीतिज्ञ आदर्शों पर चलते थे। आज हम राजनीतिक दलों की विभीषिका और उसकी अतियों से ग्रस्त होकर राष्ट्र के मूल्यों को भूल गए हैं। भारतीय राजनीति उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। चारों ओर भ्रम और मायाजाल का वातावरण है। भ्रष्टाचार और घोटालों के शोर और किस्म-किस्म के आरोपों के बीच देश ने अपनी नैतिक एवं चारित्रिक गरिमा को खोया है। मुद्दों की जगह अभद्र टिप्पणियों ने ली है। व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाठशाला के प्रधानाचार्य की तरह अपने दल के कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया कि वह झूठे एवं बेबुनियाद आरोपों की परवाह किए बिना तेजी से काम करें। जबकि विपक्षी दलों की सारी की सारी कवायद में एक अनर्थ सच्चाई के ही दर्शन हुए क्योंकि जैसे केवल चेहरे बदलने से दामन के दाग नहीं धुल जाते, वैसे ही कुछ युवा चेहरों को सामने खड़ा करने से क्रांतिकारी सोच पैदा नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार के मुद्दे को व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लगाकर पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश की जा रही है।

कई राजनीतिक दल तो पारिवारिक उत्थान और उन्नयन के लिये व्यावसायिक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक एकता की बात कौन करता है। आज देश में भारतीय कोई नहीं नजर आ रहा क्योंकि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिल की पहचान भारतीयता पर हावी हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति ने सामाजिक व्यवस्था को क्षत-विक्षत करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि सब चोर एक साथ शोर मचा रहे हैं और देश की जनता बोर हो चुकी हैं। हमें अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हुई हैं। हो सकता है कि हम परिस्थितियों को न बदल सकें पर उनके प्रति अपना रूख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। आने वाले नये राजनीतिक नेतृत्व का सबसे बड़ा संकल्प यही हो कि राष्ट्रहित में स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। व्यक्ति का क्या मूल और क्या विसात। विरोध नीतिगत होना चाहिए व्यक्तिगत नहीं। एक उन्नत एवं विकासशील भारत का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्ति नहीं, मूल्यों एवं सिद्धांतों को शक्तिशाली बनाना होगा।

बिहार की राजनीति में रौशनी का चिराग

खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में हैं। राजनीतिक कौशल एवं प्रभावी रणनीति के तहत तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूती देते हुए बिहार की राजनीति का 'चिराग' संभावना का वाहक बन रहा है। चिराग पासवान सक्षम जनप्रतिनिधि के साथ-साथ मौलिक सोच एवं संवेदनाओं के प्रतीक हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर प्रासंगिक एवं अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनाने एवं अपनी उपस्थिति का अहसास कराने का छोटी उम्र में बड़ा अनुभव है जो भारतीय राजनीति के लिये शुभता का सूचक है। लोकतंत्र का सच्चा जन-प्रतिनिधि वही है जो अपनी जाति, वर्ग और समाज को मजबूत करने के साथ देश को मजबूत करें। 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की लड़ाई लड़ने वाले चिराग 14 करोड़ बिहारियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रतिबद्ध है।

आगामी लोकसभा चुनाव-2024 चिराग का सशक्त एवं उम्मीदभरा राजनीतिक भविष्य उजागर करते हुए बिहार के शीर्ष नेतृत्व की ओर अग्रसर करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बात के संकेत इनदिनों की बिहार की राजनीति गतिविधियों से मिलने लगे हैं। गतदिनों भाजपा मुख्यालय से विनोद तावड़े ने बिहार के एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला सार्वजनिक किया, जिसमें भाजपा को 17 सीटें, जदयू को 16 सीटें तो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) के खाते में 5 सीटें गईं। वहीं उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी की पार्टी को एक-एक सीट दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जिसमें नीतीश चिराग के कंधे पर हाथ रखे आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक चित्र पहले चर्चित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी चिराग की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

> **आगामी लोकसभा चुनाव-2024 चिराग का सशक्त एवं उम्मीदभरा राजनीतिक भविष्य उजागर करते हुए बिहार के शीर्ष नेतृत्व की ओर अग्रसर करे तो कोई आश्चर्य नहीं।**

भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी बातें हर किसी मंच से होती रहती हैं लेकिन कोई दल उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देता क्योंकि उनकी नजर में युवा वोट भर हैं। राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल भीड़ और ट्रौलिंग के लिए करते रहते हैं। हालांकि इस मिथक को चिराग ने तोड़ा, 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई सीट पर 80 हजार से ज्यादा मतों से विजयी हुए थे तो एक ही संसदीय दौर में उन्होंने जनता का विश्वास इस कद्र जीता कि 2019 के चुनाव में चिराग ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। करिश्माई व्यक्तित्व वाले चिराग ने आगामी चुनाव में एनडीए को बिहार में 40 में से 40 सीटें मिलने का दावा किया है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है क्योंकि 2019 में जब एनडीए में 3 पार्टियां थी, तब 40 में से 39 सीटें जीती थीं और इस बार 5 पार्टियां हैं और लोगों का उत्साह बताता है कि बिहार में 40 सीटों के साथ एनडीए देश में 400 सीटों के लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा।

चिराग पासवान एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता है। वे भारतीय राजनीति में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले दलितों के शीर्ष नेता एवं लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र हैं। चिराग ने न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि समूची देश की राजनीति में युवा संभावनाओं को उजागर करने की खनक पैदा की है। यह वह आहट है जो भारत की राजनीति को एक नयी दिशा एवं दृष्टि प्रदत्त करेंगी। क्योंकि चिराग वोट की राजनीति के साथ-साथ सामाजिक उत्थान की नीति के चाणक्य है। वे रोजगार के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हुए बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने की मुहिम को संभव किया है। 'चिराग का रोजगार' एक मौलिक सोच की निष्पत्ति है और चिराग भारत की राजनीति में एक मौलिक सोच के प्रतीक नेता के रूप में उभर रहे हैं और मौलिकता अपने आप में एक शक्ति होती है, जो व्यक्ति की अपनी रचना होती है एवं उसी का सम्मान होता है। संसार उसी को प्रणाम करता है जो भीड़ में से अपना सिर ऊंचा उठाने की हिम्मत करता है, जो अपने अस्तित्व का भान कराता है। मौलिकता की आज जितनी कीमत है, उतनी ही सदैव रही है। जिस व्यक्ति के पास अपना कोई मौलिक विचार या कार्यक्रम है तो संसार उसके लिए रास्ता छोड़कर एक तरफ हट जाता है और उसे आगे बढ़ने देता है। मौलिक विचार तथा काम के नये तरीके खोज निकालने वाला व्यक्ति ही समाज एवं राष्ट्र की बड़ी रचनात्मक शक्ति होता है अन्यथा ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो पीछे-पीछे चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोचने का काम कोई और ही करे। चिराग ने भारत की राजनीति में युवा पीढ़ी के लिए कुछ नया सोचा है, कुछ मौलिक सोचा है, तो सफलता निश्चित है। वे इसी सोच से प्रदेश की राजनीति से केन्द्र की राजनीति की ओर अग्रसर होकर सफल नेतृत्व देने में सक्षम साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

लोजपा अब पूरी तरह युवाओं के हाथ में है। चिराग युवा हैं, सक्षम है, प्रखर वक्ता है, कुशल संगठनकार एवं प्रबंधक हैं और विगत में उन्होंने अनेक अवसरों पर अपनी इन क्षमताओं के साथ-साथ निर्णायकता साबित की है। कई मौकों पर यह बात सामने आई है कि बिहार के साथ-साथ केंद्रीय राजनीति के दांव-पेच और समीकरणों को भी वह अच्छी तरह जानने-समझने लगे हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दलित राजनीति के अगले ध्वजवाहक बनने और अपने लक्षित मतदाता समूह में पिता जैसी स्वीकार्यता पाने की होगी। चिराग नई लकीर खींचने में पारंगत है, वे अपने पिता की प्रतिछाया ही न बनकर कुछ नये प्रतिमान स्थापित करेंगे, राजनीति की नई परिभाषाएं गढ़ंगे। क्योंकि वे विपरीत स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करके भरोसा और विश्वास का वातावरण निर्मित करने में दक्ष है। युवापीढ़ी और उनके सपनों का मूर्च्छित होना और उनमें निराशा का वातावरण निर्मित होना- एक सबल एवं सशक्त राष्ट्र के लिये एक बड़ी चुनौती है। चिराग ने यह अनुभव किया, यह उनकी सकारात्मक राजनीति एवं मानवतावादी सोच का ही परिणाम है। चिराग इस मामले में अन्य क्षत्रप या नेता पुत्रों से थोड़ा अलग इसलिए भी हैं कि उनका नजरिया और अंदाज भविष्योन्मुखी और विकासवादी प्रतीत होता है। यही कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग में राजनीतिक संभावनाओं को गहराई से समझा है। इन सबके बावजूद यक्ष प्रश्न यह है कि क्या चिराग अपने पिता की दलित राजनीति की विरासत को कोई नया आयाम दे पाएंगे।

लालू की रणनीति एनडीए पर भारी

▪ ओमप्रकाश अश्क

लालू यादव की रणनीति बिहार में एनडीए पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव की मेहनत और लालू के ज्ञान के समन्वय ने एनडीए की आसान राह को अब मुश्किल बना दिया है। हां, यह एहसास लालू अब जरूर करा देते हैं कि गठबंधन चलाने का तरीका उन्होंने भाजपा से सीखा है। गठबंधन सिर्फ सलाह-मशवरे से नहीं चलता। इसमें भी सुप्रीमो की भूमिका जरूरी है। सुप्रीमो यानी सबकी सुने, मगर करे अपनी। बिहार में पहले से चले आ रहे महागठबंधन में फैसले पहले भी होते थे। इसके लिए सबकी सहमति जरूरी होती थी। रूठे को मनाना पड़ता था। यह दौर तब था, जब लालू जेल में सजा काट रहे थे या बीमार थे। अब वे स्वस्थ हैं और सक्रिय भी। स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही के बावजूद वे मंच पर भाषण कर आते हैं। गठबंधन की बैठकों में शामिल होते हैं। नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वे मिलते भी हैं। इतना ही नहीं, जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए वे सक्रियता भी दिखाते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी को सियासत की बारीकियां भी बताते हैं।

बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह अपनी पार्टी आरजेडी को लालू हांकते रहे हैं, उसी अंदाज में वे गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी हांक रहे हैं। आश्चर्य कि तमाम उछल-कूद के बावजूद लालू अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं। लालू पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार की सिर्फ कटु आलोचना ही नहीं करते, बल्कि पीएम और एनडीए नेताओं के वार पर पलटवार भी करते हैं। खुद से अधिक यह काम वे अपने बेटे तेजस्वी से कराना बेहतर समझते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा या एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने लालू के परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया था। पीएम मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हों, सभी इस मुद्दे को ऐसे उछाल रहे थे, जैसे इसी एक मुद्दे से बिहार की सभी 40 सीटें झोली में खुद ब खुद आ जाएंगी। नीतीश कुमार भी अपने को भारत रत्न से हाल ही नवाजे गए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सच्चा अनुयायी इसीलिए कहते थे कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। नीतीश ने भी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि उनका एक ही बेटा है, जिसकी दूर-दूर तक राजनीति में रुचि नहीं है। भाजपा के नेताओं का तो परिवारवादी बता कर लालू-तेजस्वी का नाम लिए बगैर खाना भी शायद ही हजम होता होगा।

लालू ने बेटे तेजस्वी से इसका ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। यहां तक कि पीएम मोदी की जुबान भी गुरुवार को जमुई की सभा में नहीं खुली। आरजेडी को यह अंदेशा रहा होगा कि जमुई की सभा में मोदी एक बार फिर लालू के परिवारवादी राजनीति

पर बोलेंगे ही। लालू के ज्ञान से तेजस्वी का दिमाग खुला और उन्होंने एनडीए में वंशवादी राजनीतिज्ञों की फेहरिस्त ही मोदी के आगमन से पहले जारी कर दी। उन्होंने सवाल भी उछाल दिया कि इस पर अब एनडीए वाले क्या कहेंगे। शायद तेजस्वी की उस सूची का ही असर था कि न सम्राट चौधरी की इस मुद्दे पर जुबान खुली और न पीएम मोदी के मुंह से इस बारे में कुछ निकला।

सियासत में लालू की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, यह आरजेडी का आदमी तो यकीनन कहेगा। पर, उनके विरोधियों की राजनीति भी लालू नाम के बिना अधूरी रहती है। कोई परिवारवाद के बहाने लालू का नाम लेता है तो कई भ्रष्टाचार के जिक्र के क्रम में उनका उल्लेख करते हैं। तीन दशक बीत जाने के बाद भी जंगल राज का जिक्र कर जीत की उम्मीद लालू के विरोधी पाले हुए हैं। ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि नब्बे के दशक के जंगल राज का दुःस्वप्न कबका लोगों की जेहन से उतर चुका है। अब तो जिनकी उम्र 34 साल की हो गई होगी, उन्हें सिर्फ इतिहास की कहानियों की तरह जंगल राज की जानकारी होगी। और, ऐसे 34 साल की उम्र वाले वोटरों की तादाद बिहार में अभी 47 प्रतिशत है। यह वही पीढ़ी है, जिसे पुरानी बातें बकवास लगती हैं। इन्हें तो पढ़ाई, करियर और इंप्लॉयमेंट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। और, इस मामले में वे तेजस्वी यादव को इनमें अधिकतर अपना आइकन मानने लगे हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी किसी चारा चोर के बेटे हैं। किसी सजायाफ्ता की संतान हैं। किसी जमाने में जंगल राज के उनके माता-पिता नायक रहे हैं। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी के बदले जमीन लेने का उनके पिता पर आरोप है।

टिकट बंटवारे को लेकर हड़बोंग मचाने वाले नीतीश ने साथ छोड़ दिया तो लालू ने मान मनौव्वल नहीं की। महागठबंधन में शामिल दल जितनी सीटों की मांग को लेकर कूद फांद कर रहे थे, उन्हें लालू ने अपने आकलन से गिनी-चुनी सीटें दीं। क्षेत्र भी अपने हिसाब से बांटे। नापसंदगी के बावजूद न कांग्रेस की जुबान खुली और न अन्य दलों की। कांग्रेस की पसंद होने के बावजूद लालू ने पप्पू यादव को पूर्णिया में पटक दिया। कटिहार में टिकट नहीं मिलने से खफा करीम को एक मुलाकात में मना लिया। वे आरजेडी का बागी उम्मीदवार बनने को बेचैन थे। कन्हैया कुमार को रोकने के लिए कांग्रेस को ऐसी कोई सीट ही नहीं दी, जो उन्हें सूट करे। ओवैसी की एआईएमआईएम की वजह से एम-वाई समीकरण के वोटों में बिखराव का खतरा था। एक बार की बातचीत में ओवैसी लालू के मुरीद हो गए। बिहार में कभी सात, कभी 11 और कभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कहने वाले एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम अब कह रहे कि किशनगंज को छोड़ सीमांचल की किसी भी सीट पर पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी। बाकी के बारे में भी बाद में निर्णय लिया जाएगा।

लालू की भौतिक मौजूदगी के कारण बिहार में इस बार लोकसभा का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं लगता। 40 की बात तो छोड़ दीजिए, 39 सीटों का पिछला रिकॉर्ड कायम रखने में भी एनडीए को कई पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। अभी तो परिवारवाद के वार पर पलटवार कर तेजस्वी ने इस मुद्दे को ही गायब कर दिया है। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोपों की भी हवा निकालने की तरकीब लालू अपने लाल तेजस्वी को सिखा दें तो कोई आश्चर्य नहीं।

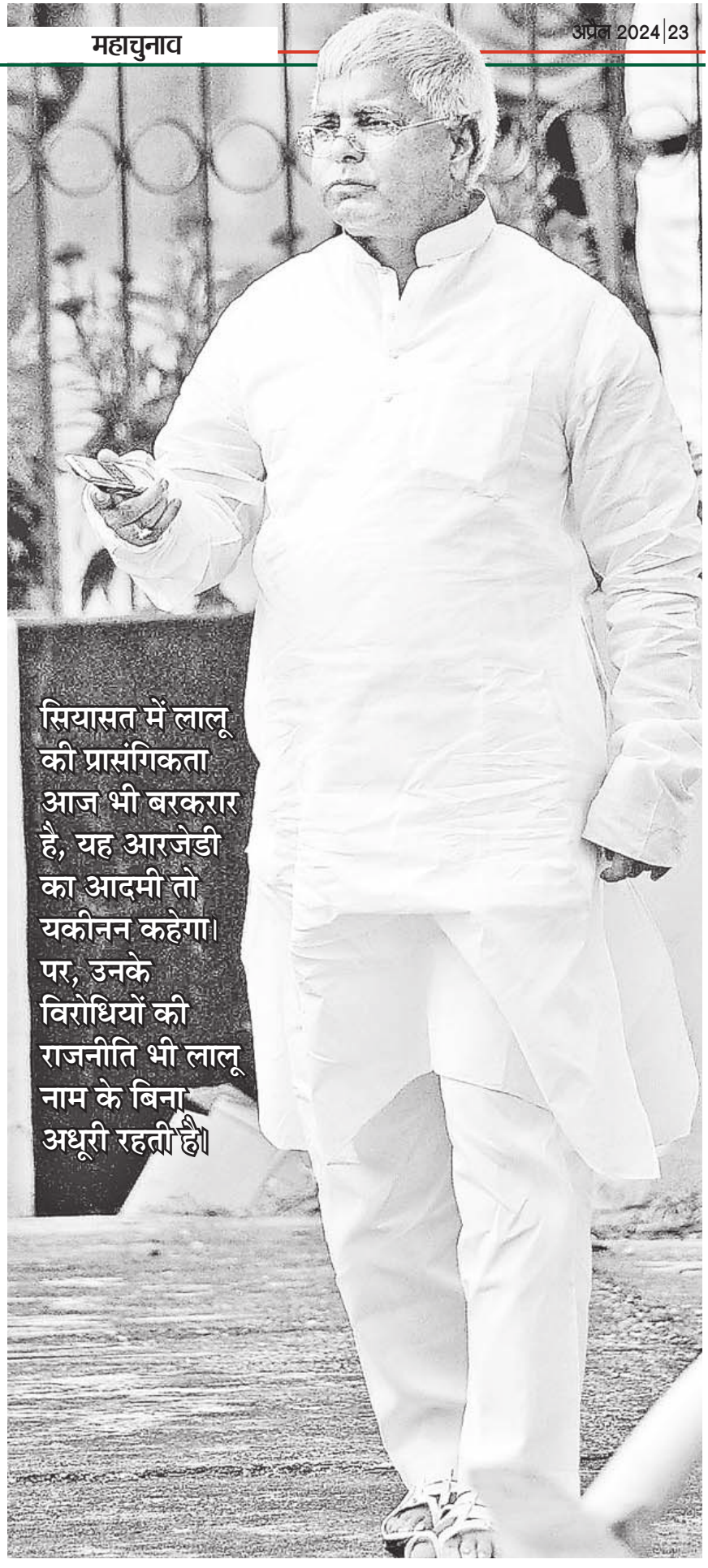

इंडी गठबंधन ने नौ और एनडीए ने सात सीटों पर बदले प्रत्याशी, सभी पर आमने सामने का टक्कर

सत्येन्द्र

मिशन 2024 को लेकर झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर विजय दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी मुक्कमल तैयारी कर ली है। झारखंड में हानेवाले लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर होने की संभवना है। राज्य की 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन ने अब तक 12 सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इनमें से नौ सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। तीन सीट पर पिछले चुनाव में उतरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जबकि दो सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। जिन नौ सीटों पर प्रत्याशी बदले गये हैं, उनमें कांग्रेस कोटा की सात में से चार सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने हजारीबाग, धनबाद, गोड्डा व चतरा में अपना प्रत्याशी बदल दिया है। जबकि खूंटी व लोहरदगा में फिर से 2019 वाले प्रत्याशी पर ही दांव लगाया है। राजधानी रांची की सीट पर फिलहाल प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर कांग्रेस ने सस्पेंस बरकारार रखा है। इस सीट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के दो नेता क्रमशः पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आमने-सामने है। कांग्रेस रांची सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएगी वह भविष्य के गर्भ में है।

वहीं झामुमो ने भी दुमका व गिरिडीह में प्रत्याशी बदल दिया है। वर्ष 2019 की चुनाव में चाईबासा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, पर इस वर्ष यह सीट गठबंधन के तहत झामुमो को चली गयी है। झामुमो ने विधायक एवं पूर्व मंत्री जोबा माझी को प्रत्याशी बनाया है। झामुमो अपने हिस्से के पांच में से चार सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इनमें से तीन पर नये प्रत्याशी हैं। जमशेदपुर में झामुमो ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पिछले चुनाव में झामुमो ने चंपाई सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस वर्ष उनके चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में जमशेदपुर में भी प्रत्याशी का बदलाव लगभग तय है। वर्ष 2019 में पलामू में राजद ने घूरन राम को प्रत्याशी बनाया था। इस वर्ष राजद ने ममता भुइयां को प्रत्याशी बनाया है। इस बार कोडरमा सीट भाकपा माले को दी गयी है। भाकपा माले ने यहां से विधायक विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में यह सीट गठबंधन के तहत झाविमो को दी गयी थी। गोड्डा सीट भी पिछली बार झाविमो को दी गयी थी, इस बार यहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इस सीट से कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडेय को अपना उम्मीदवार बनाया है। **इंडिया गठबंधन से छह विधायक लड़ रहे चुनावः** झारखंड में इंडिया गठबंधन के टिकट पर छह विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें मांडू के विधायक जेपी पटेल हजारीबाग, बगोदर के विनोद सिंह कोडरमा, टुंडी के मथुरा महतो गिरिडीह, महगामा की दीपिका पांडेय सिंह गोड्डा, मनोहरपुर की जोबा माझी चाईबासा व शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

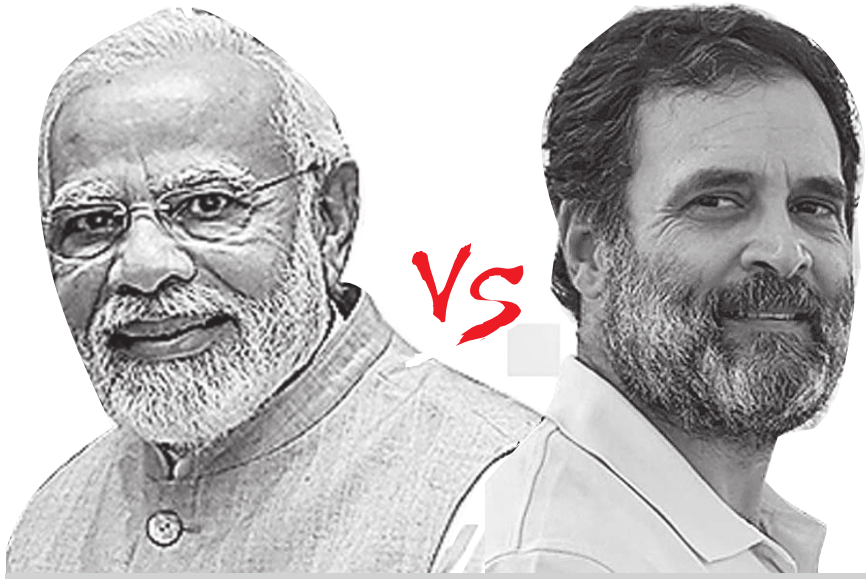

एनडीए और इंडिया में कौन, किसके मुकाबले

लोकसभा क्षेत्र	एनडीए	इंडिया गठबंधन
राजमहल	ताला मरांडी (पूर्व विधायक)	विजय हांसदा (सांसद)
दुमका	सीता सोरेन (विधायक)	नलिन सोरेन(विधायक)
गोड्डा	निशिकांत दूबे (सांसद)	दीपिका पांडेय सिंह (विधायक)
चतरा	कालीचरण सिंह	केएन त्रिपाठी (पूर्व विधायक)
पलामू	बीडी राम (सांसद)	ममता भूइया
सिंहभूम	गीता कोड़ा (सांसद)	जोबा मांझी (विधायक)
रांची	संजय सेठ (सांसद)	यशस्विनी साहय
खूंटी	अर्जुन मुंडा (सांसद)	कालीचरण मुंडा (पूर्व विधायक)
हजारीबाग	मनीष जायसवाल (विधायक)	जेपी पटेल (विधायक)
लोहरदगा	समीर उरॉव (रास सांसद)	सुखदेव भगत (पूर्व विधायक)
धनबाद	ढुलू महतो (विधायक)	अनुपमा सिंह
जमशेदपुर	विद्युत वरण महतो (सांसद)	तय नही
कोडरमा	अन्नपूर्णा देवी (सांसद)	विनोद सिंह (विधायक)
गिरिडीह	चंद्र प्रकाश चौधरी (सांसद)	मथुरा महतो (विधायक)

दो सीट पर नाम की घोषणा नहींः कांग्रेस व झामुमो ने अपने-अपने हिस्से की एक-एक सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने रांची व झामुमो ने जमशेदपुर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने रांची से 2019 में सुबोधकांत सहाय को प्रत्याशी बनाया था। इस वर्ष अब तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। जबकि झामूमो ने 2019 में जमशेदपुर से चांई सोरेन का प्रत्याशी बनाया था। इस बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चंपाई सोरेन को लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं के बराबर है।

भाजपा ने भी सात प्रत्याशी बदले : भाजपा ने भी इस लोकसभा चुनाव में सात प्रत्याशी बदले हैं। भाजपा ने हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल, दुमका से सीता सोरेन, लोहरदगा से समीर उरांव, सिंहभूम से गीता कोड़ा, धनबाद से ढुलू महतो, चतरा से कालीचरण सिंह और राजमहल से ताला मरांडी को प्रत्याशी बनाया है।

भाजपा से तीन विधायक मैदान मेंः भाजपा ने लोकसभा चुनाव में तीन विधायकों को मौका दिया है। इनमें हजारीबाग से मनीष जायसवाल, धनबाद से ढुलू महतो और दुमका से सीता सोरेन हैं। हालांकि सीता सोरेन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह बीजेपी में शामिल होने से पूर्व जेएमएम की विधायक थी। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।

कल्पना प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरी

झारखंड मुक्ति मोर्चा बदल रहा है। पार्टी के काम करने के तरीके में बदलाव हो रहा है। ये सभी बदलाव कल्पना सोरेन के पार्टी में सक्रिय होने के बाद देखने को मिल रहा है। कल्पना सोरेन पार्टी में एक मजबूत चेहरा बनकर उभरी हैं। ऐसे में चर्चा तेज है कि आने वाले समय वो गठबंधन का भी अहम चेहरा बन सकती है।

इसी माह अप्रैल को एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। पिछले कुछ महीनों में कल्पना सोरेन झारखंड में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। शुरुआती दिनों में राजनीतिक मंचों से उनके चेहरे में दिखने वाली झिझक भी कम हुई है। जेएमएम की विचारधारा और पार्टी की नींव को अब वो समझ रही हैं।

अपने भाषणों में कल्पना सोरेन दिशोम गुरू शिबू सोरेन के संघर्ष, जेएमएम के वजूद, आदिवासी भावनाओं की चर्चा करती हैं। चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर दावा किया है कि राज्य की मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बन सकती हैं। कल्पना सोरेन एक मजबूत राजनेता के रूप में उभर रही है। मजबूत होते उनके कदम के साथ-साथ पार्टी के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

जेएमएम में क्या आंतरिक विरोध खत्म हो गया है? पुराने नेताओं ने क्या कल्पना को स्वीकार कर लिया है? अगर जेएमएम मजबूत हो रही है तो इसका भविष्य क्या है? जेएमएम 21 अप्रैल को उलगुलान रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली की जिम्मेदारी कल्पना सोरेन के कांधे पर है, इसके क्या मायने हैं ?

» जेएमएम में क्या आंतरिक विरोध खत्म हो गया है?

» पुराने नेताओं ने क्या कल्पना को स्वीकार कर लिया है?

» अगर जेएमएम मजबूत हो रही है तो इसका भविष्य क्या है?

एक-एक कदम राजनीति की तरफ बढ़ाती गईं : कल्पना सोरेन के राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए जरूरी है कि अब तक राजनीति में उनके हर एक कदम को समझा जाए। तारीख 30 जनवरी 2024 विधायक दल की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन शामिल हुई। इस तस्वीर के साथ चर्चा तेज हो गई की कल्पना सोरेन ही हेमंत के बाद मुख्यमंत्री बनेंगी। परिस्थिति बदली हेमंत गिरफ्तार हुए तो मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आया चंपाई सोरेन का।

कल्पना सोरेन बैकफुट पर रहीं, लेकिन उन्हें सामने लाने की तैयारी पार्टी के अंदर चलती रही। 6 फरवरी को हेमंत सोरेन के एक्स पर एक ट्वीट आया। लिखा था- जब तक झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार और बीजेपी के षड्यंत्र को परास्त कर हम सब के बीच नहीं आ जाते, तब तक उनका यह एकाउंट मेरे यानी उनकी जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा।

हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया के माध्यम से मुखर होती कल्पना सोरेन की आवाज ने यह साफ कर दिया कि वह बैकफुट पर खड़े होकर सब नहीं देखेंगी। अपनी बात और विरोधियों पर निशाना साधने के लिए कल्पना ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

3 अप्रैल 2023 अपने जन्मदिन के मौके पर कल्पना सोरेन ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, झारखंड वासियों और झामुमो परिवार के असंख्य कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर कल से मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हूं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते तब तक मैं उनकी आवाज बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपसे साझा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। 4 अप्रैल को गिरिडीह में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। अब कल्पना सोरेन, सीट बंटवारे से लेकर पार्टी के हर रणनीतिक फैसले में शामिल हो रही है।

झारखंड में जेएमएम की उलगुलान रैली को लेकर राजनीति तेज है। इस रैली की पूरी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन के कंधे पर है। उद्देश्य भी साफ है, हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन से अधिक अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने की चर्चा हो रही है। केजरीवाल से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होना है। इस रैली को राज्य में एक साथ कई मुद्दों को साधने का माध्यम माना जा रहा है।

रांची लोकसभा सीट से सुबोधकांत की बेटी यशस्विनी को मौका

रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है। पार्टी ने सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। वहीं गोड्डा में घोषित प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह की जगह अब वहां से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले पार्टी में कई दौर की बैठक हुई।

सुबोधकांत की बेटी यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इस चुनाव में नए लोगों को मौका दे रही है। इस ऐलान के साथ ही पार्टी ने ने राज्य में अपने हिस्से की सभी सात सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

टिकट मिलने के बाद यशस्विनी सहाय ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह अवसर मिला है। मैं राजनीति में कदम रखने को लेकर उत्साहित हूं और अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए कदम रख रही हूं। मैं भी समाज सेवा करना चाहती हूं, मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें काम करते देखा है। मैं एक वकील के तौर पर भी बाल अधिकार के संरक्षण के लिए काम किया है।

मेरी रगों में राजनीति की समझ है। मैंने अपने पिता को देखा है। मैं महिला और युवाओं की समस्या को आगे रख सकूंगी। मेरा विजन समस्याओं का हल करना है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी पर यशस्विनी सहाय ने कहा कि हमें युवाओं की समस्याओं का हल करना होगा। मैं रांची के युवाओं से जुड़ने और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगी। चुनावी रणनीति पर उन्होंने कहा कि अभी मेरा जुड़ाव जरूरी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय की बेटी होने के साथ-साथ उनकी अलग पहचान भी है। वह बाल श्रम, यौन शोषण पर रोक लगाने के लिए काम करती रही हैं। यशस्विनी सहाय ने मुंबई से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। इसके बाद ट्रांस्नेशनल क्राइम एंड जस्टिस (यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट), टुरिन, इटली से लॉ में मास्टर डिग्री ली। वर्तमान में मुंबई फैमिली कोर्ट और मुंबई सेशन कोर्ट में बतौर वकील सेवाएं दे रही हैं।

वह राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं। वे मरूनालनी देशमुख (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ जुड़कर लीगल एडवाइजर के रूप में वहां भी सेवाएं दे रही हैं। इसके तहत वह विशेष रूप से झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रही हैं। हाल के दिनों में पीड़ित मानवता के सेवार्थ झारखंड में उनके कार्यों को सराहा गया है। घोषणा के पूर्व ही रांची में उलगुलान न्याय रैली के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यशस्विनी सहाय को बधाई दी। उन्हें क्षेत्र में काम करने के लिए कहा था।

प्रदीप यादव ने कहा मैं कांग्रेस का सिपाही- मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर चलेंगे, नाराजगी कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जनता चाहती है कि हमारी समस्या को रखने वाला कोई और हो। नेता तभी रहेगा जब जनता से संपर्क रहेगा। गोड्डा में काफी मुद्दे हैं। मेरे लिए सिर्फ जनता की सेवा ही मुद्दा है. दीपिका पांडेय सिंह का गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हो रहे विरोध और यादव या अंसारी में से किसी को टिकट देने की मांग के बाद ही कांग्रेस नेतृत्व ने वहां से उम्मीदवार बदल दिया और प्रदीप यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। आलाकमान ने अंततः प्रदीप यादव पर भरोसा जताया।

कौन कहां से : कांग्रेस ने हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी से अपना उम्मीदवार घोषित किया था. पार्टी ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग सीट से जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया है।धनबाद से अनुपमा सिंह, गोड्डा से प्रदीप यादव और चतरा से पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है।

गोड्डा में निशिकांत को टक्कर देंगे प्रदीप यादव

यशस्विनी सहाय ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह अवसर मिला है। मैं राजनीति में कदम रखने को लेकर उत्साहित हूं और अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए कदम रख रही हूं। मैं भी समाज सेवा करना चाहती हूं, मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें काम करते देखा है। मैं एक वकील के तौर पर भी बाल अधिकार के संरक्षण के लिए काम किया है।

ईरान का अभूतपूर्व हमला इजराइल ने किया नाकाम

इस्राएल का कहना है कि उसने ईरान के अभूतपूर्व हमले को "नाकाम" कर दिया है। ईरान ने देर रात 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इस्राएल पर हमला किया। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इस्राएल के बाहर ही बेकार कर दिया गया।

मध्य पूर्व में अलग-अलग मोर्चे पर लंबे समय से चल रही अशांति ईरान के इस्राएल पर हमले के बाद और ज्यादा बढ़ गई। ईरान समर्थित गुटों और उसके सहयोगियों ने शनिवार की रात इस्राएल पर हमला किया। यरुशलम के अलग-अलग हिस्सों में लगातार सायरन और आकाश में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह सिलसिला सुबह तक जारी था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएल को "अटल" सहयोग की बात दोहराई है और इस संकट के गहराने पर अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रपति बाइडेन डेलावेयर का दौरा बीच में ही रद्द कर वाशिंगटन पहुंच गए। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी जी 7 देशों की भी बैठक बुलाने की बात कही.

ईरान की तरफ से इस हमले की आशंका पहले से ही अमेरिका समेत सभी पक्षों को थीं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हवाई हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया गया था। इस हमले में ईरान के दो जनरलों समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इस्राएल पर लगाया था और इसका जवाब देने की बात कही थी। इस्राएल ने इस हमले को ना स्वीकार किया है ना ही इससे इनकार.

ड्रोन और मिसाइलों से हमला : देर रात इस्राएल ने कहा कि ईरान ने, "200 से ज्यादा किलर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है." इस्राएली सेना का कहना है कि उसने सभी हवाई खतरों को बीच रास्ते में ही रोकने के लिए दर्जनभर से ज्यादा लड़ाकू विमान तैयार रखे थे। इस्राएल ने हमला नाकाम होने के दावे के साथ ही इसे अपनी जीत बताया है। इस्राएली सेना, अमेरिका और दूसरे सहयोगियों के साथ मिल कर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर रही थी। सुबह इस्राएल सेना ने कहा कि 99 फीसदी ड्रोनों और मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डानियल हागरी ने टेलीविजन पर प्रसारित संदेश में कहा, "ईरानी हमला नाकाम हो गया."

जर्मन विदेश नीति के मूल में है इस्राएल की सुरक्षाः जर्मनी : ईरान की रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस बात की पुष्टि की है कि सीरिया में कॉन्सुलेट पर हुए हमले के जवाब में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि धीमी गति के ड्रोन हमलों के करीब एक घंटे बाद बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। तेहरान के फलीस्तीन चौक पर सैकड़ों ईरानी लोग जमा हो कर फलीस्तीन के समर्थन में झंडे लहरा रहे थे। इलाके में ईरान के सहयोगियों ने भी इस हमले में हिस्सा लिया। यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने भी इस्राएल के तरफ ड्रोन से हमला किया। लेबनान के हिज्बुल्लाह संगठन का भी कहना है कि उसने गोलन पहाड़ियों में इस्राएली ठिकानों पर उसी समय रॉकेट दागे हैं.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक नेगेव के रेगिस्तान में इस्राएली एयर बेस को "काफी नुकसान" हुआ है। हालांकि इस्राएली आर्मी का कहना है कि नुकसान बहुत मामूली है.

उधर ईरान का कहना है कि हमले ने "अपने सारे उद्देश्य पूरे" कर लिए हैं। ईरानी सेना के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने ईरान की सरकारी टेलीविजन चैनल से कहा, "ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस ...पिछली रात से आज सुबह तक पूरा हुआ और अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करने में सफल रहा." ईरान का कहना है कि उसने यह हमला एक अप्रैल को सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर हुए ---हमले के बाद "आत्मरक्षा" में किया.

बाघेरी का कहना है कि हमले में एक इंटेलिजेंस सेंटर और उस एयरबेस को निशाना बनाया है जहां से कॉन्सुलेट पर हमले के लिए इस्राएली एफ-35 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी। बाघेरी ने यह भी कहा, "इन दोनों सेंटरों को ध्वस्त कर बेकार कर दिया गया है। हम इस ऑपरेशन को पूरा मानते हैं और हमारी राय में यह खत्म हो गया है." इस्राएल का कहना है कि हमले में हुआ नुकसान बहुत मामूली है.

अमेरिका का सहयोग *: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह इस्राएल के साथ ईरान के विवाद से खुद को अलग रखे। मिशन की तरफ से कहा गया है, "यह ईरान और कपटी इस्राइली सत्ता के बीच लड़ाई है जिससे अमेरिका को जरूर अलग रहना चाहिए." मिशन की तरफ से जारी बयान में यह भी उम्मीद जताई गई है कि ईरान के राजनयिक मिशन पर हमले की सजा देने के लिए उठाया गया ईरान का कदम इस विवाद को और नहीं भड़काएगा, "यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए."*

अमेरिकी राष्ट्रपति के अल्टीमेटन से बदले नेतन्याहू के सुर : हालांकि ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने इस्राएल को उसकी तरफ आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने मे मदद दी। बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने, "इस्राएल को लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में मदद दी है." बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत में कहा, "इस्राएल ने अभूतपूर्व हमले के खिलाफ भी खुद को बचाने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर अपने दुश्मनों को यह साफ संदेश दिया है कि वे इस्राएल की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकते." न्यूज आउटलेट आक्सियोस का कहना है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि वह ईरान के खिलाफ जवाबी हमले का विरोध करेंगे और उन्हें "जीत को स्वीकार" करना चाहिए.

एनटीपीसी का वर्ष 2024 में कोयला उत्पादन व डिस्पैच में शानदार प्रदर्शन

एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की अग्रणी एकीकृत विद्युत उपयोगिता ने वित्त वर्ष '24 में 31 अप्रैल तक 34.39 एमएमटी के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के साथ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित अपनी पांच परिचालन कैप्टिव कोयला खानों से शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है और 48.21% की महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ।

कंपनी ने वित्त वर्ष '24 में 34.15 एमएमटी का प्रभावशाली कोयला डिस्पैच हासिल किया, जिसमें 55.50% YoY ग्रोथ की वृद्धि हुई. इसके अलावा, इसने INR 1640 करोड़ का कैपेक्स प्राप्त करके अपने कैपेक्स उपयोग लक्ष्य को पार कर लिया.

इसके अलावा, एनटीपीसी कोयला खनन ने क्रमशः 1.8 एलएमटी और 1.29 एलएमटी का एक दिन का सबसे अधिक कोयला उत्पादन और प्रेषण हासिल किया। कोयला उत्पादन केरेनदारी कोयला खनन परियोजना से शुरू हो गया है, जो एनटीपीसी की 5 वीं कैप्टिव खान है। एनटीपीसी की सभी पांच प्रचालनात्मक कोयला खदानों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और उनसे अधिक कार्य कर लिया है तथा भविष्य में नए मानक स्थापित करने के लिए कमर कस ली है।

दुलंगा कोयला खनन परियोजना ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से 5 स्टार रेटिंग हासिल की है और यह पिछले तीन वर्षों से देश की शीर्ष 3 खानों में से एक है।

एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल), एनटीपीसी लि के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को कोयला मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी को पहले आबंटित 6 कोयला खानों के लिए संशोधित आबंटन करार प्राप्त हुए हैं। एनएमएल ने कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत झारखंड राज्य में उत्तरी धाडू (पूर्व) कोयला ब्लॉक भी जीता है। इसके अलावा, NML को CRISIL & CARE से AAA की क्रेडिट रेटिंग मिली है।

आज की तारीख तक, एनटीपीसी ने उत्पादन की शुरुआत से अपनी पांच प्रचालनात्मक कैप्टिव कोयला खानों (अर्थात झारखंड में पकरी बरवाडीह और चट्ट-बरियातू और केरेनदारी कोयला खदानों, ओडिशा में दुलंगा कोयला खान और छत्तीसगढ़ में तलाईपल्ली कोयला खान) से लगभग 103+ मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कोयले का उत्पादन किया है। एनएमएल एनटीपीसी थर्मल उत्पादन का 13% ईंधन भर रहा है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है और प्रति वर्ष 100 मिलियन टन की क्षमता तक पहुंचने की कल्पना करता है।

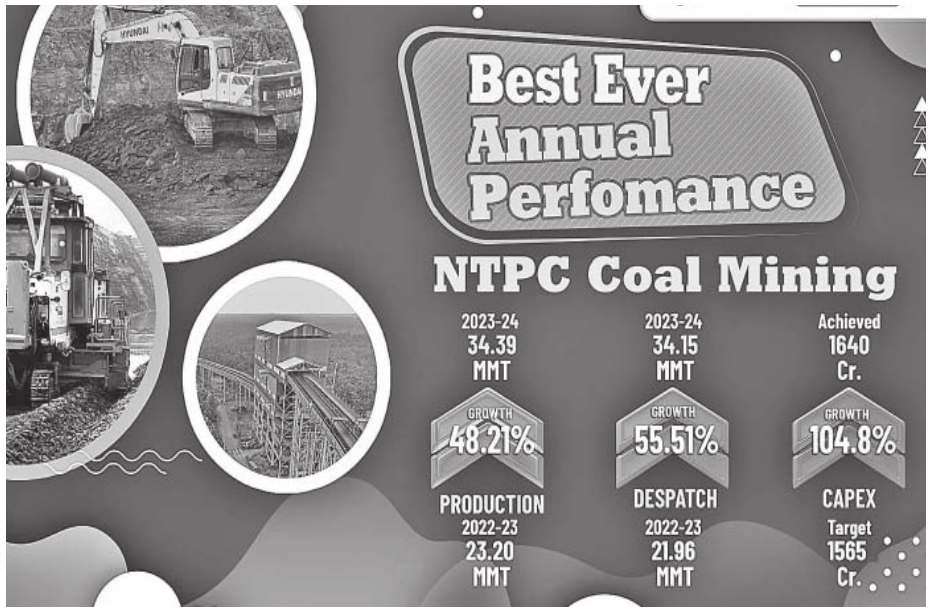

कैप्टिव खदानों से वित्त वर्ष 2025 में 40 एमएमटी कोयला उत्पादन का लक्ष्य

भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी कैप्टिव खदानों से 40 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य एनटीपीसी को पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कैप्टिव कोयला उत्पादन में 17% की महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने में मदद करेगा।

इससे वित्त वर्ष 2025 में कैप्टिव खदानों के माध्यम से कोयले की 15% से अधिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी, जिससे बिजली प्रमुख के लिए ईंधन सुरक्षा मजबूत होगी।

कंपनी ने 31 अप्रैल 2024 के अंत तक 34.15 एमएमटी का प्रभावशाली कोयला प्रेषण हासिल किया और कोयला उत्पादन 34.38 एमएमटी रहा।

यह उत्कृष्ट प्रदर्शन एनटीपीसी की अपनी कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

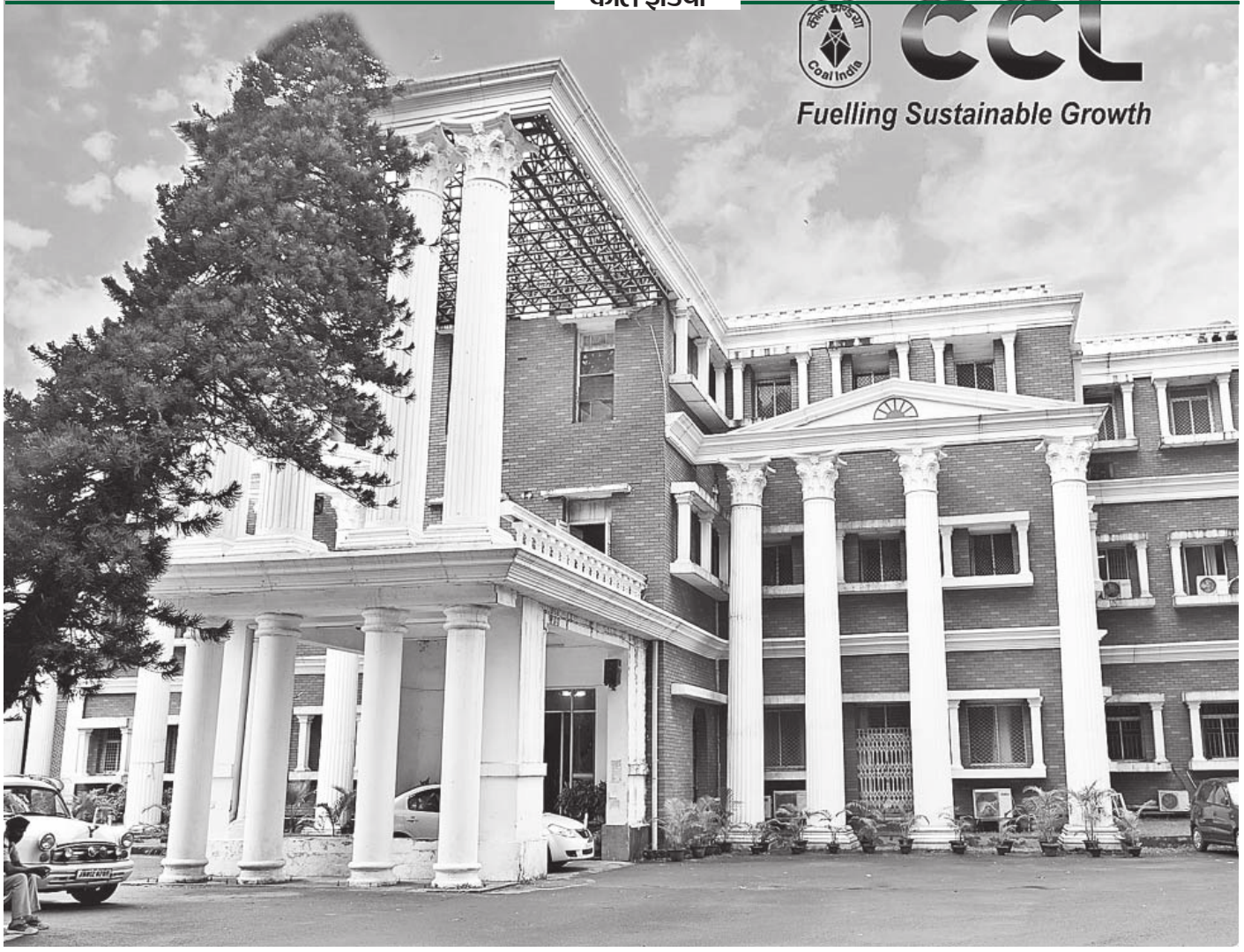

सतत विकास की कहानी बयां करता आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त क्षेत्र

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। झारखंड स्थित इस कंपनी का मुख्यालय रांची में है। वर्तमान में यह कंपनी झारखंड राज्य के आठ जिलों में खनन गतिविधियां कर रही है। कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसे वर्ष 2007 में श्रेणी-1 में एक 'मिनीरत्न कंपनी' का दर्जा प्राप्त हुआ। सीसीएल झारखंड राज्य के आठ जिलों में अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का पालन करते हुए राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है जिनमें में रांची, रामगढ़,चतरा,लातेहार, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो में सफलतापूवर्क संचालित है।

सीसीएल राज्य के खजाने में सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक है और झारखंड राज्य में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। सीसीएल का देश के कोयला उत्पादन में बहुमूल्य योगदान है। वर्तमान में सीसीएल में 36 - जिनमें 3 भूमिगत एवं 33 खुली खदानें, 5 वाशरियां जिनमें 4 कोकिंग (कथारा, रजरप्पा, केदला एवं स्वांग) और 1 नॉन-कोकिंग (पिपरवार) संचालित हो रही हैं। सीसीएल के 7 कोलफील्ड्स (पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह और हुंटार) हैं।

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थाई विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरने का संकल्प लिए सीसीएल का उद्देश्य सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययिता पूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला तथा कोयला उत्पाद का सुनियोजित मात्रा में उत्पादन और विपणन करना है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृतसंकल्पित है। ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की मांग को पूरा करने में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसी कड़ी में झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का एक प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है। आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र सीसीएल की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त नामक दो परियोजनाएं है। इसमें चन्द्रगुप्त परियोजना का परिचालन शुरू होना अभी बाकी है।

वित्त वर्ष 2023-24 में इस क्षेत्र ने 22.58 मिलियन टन का कोयला उत्पादन कर सीसीएल को अपने निर्धारित लक्ष्य को पार करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही, 28.58 मिलियन क्यूबिक मीटर का ओवरबर्डन रिमूवल और 21.67 मिलियन टन कोयले का प्रेषण भी किया है। ज्ञातव्य हो कि सीसीएल झारखंड राज्य सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व का योगदान देती है। यह क्षेत्र राज्य और देश के ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं। आम्रपाली परियोजना में लगभग 467 मिलियन टन कोयले का का भंडार है, वही दूसरी परियोजना चंद्रगुप्त में 527 मिलियन टन कोयले का भंडार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, परियोजना का लक्ष्य 24 मिलियन टन का कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।

आम्रपाली-चंद्रगुप्त ओपन कास्ट परियोजना शॉवेल एवं डम्पर संयोजन के माध्यम से सरफेस माइनर (ब्लास्टिंग फ्री तकनीक) एवं अन्य आधुनिक मशीनों का उपयोग करके पर्यावरण-अनुकूल खनन कर रहा है। यह परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिकतम कोयला उत्पादन करने में सफल रही है।

यह क्षेत्र अपनी परिचालन उपलब्धियों के अलावा,कमान क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास और कौशल प्रशिक्षण इत्यादि लोक कल्याणकारी पहल से क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

स्वास्थ्यः सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने टंडवा ब्लॉक, चतरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है, जो गंभीर मरीजों के इलाज में काफी मददगार है। साथ ही, नियमित रूप से विभिन्न स्थानों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है जिसका लाभ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उठा रहे है। क्षेत्र के ये गतिविधियां सामुदायिक विकास और कल्याण के लिए परियोजना के समर्पण को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, टंडवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी) के हिस्से के रूप में सदर अस्पताल, चतरा में आईसीयू बेड स्थापित किए गए हैं। शिक्षाः सीसीएल ने विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के लिए 30 सरकारी स्कूलों में 54 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की हैं । साथ ही कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए 500 डेस्क बेंच एवं बच्चों के परिवहन के लिए 52-सीटर स्कूल बस भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 20 आरओ युक्त सयंत्र स्थापित किया हैं। सीसीएल के इन पहलों से स्कूल में नामांकन दर में उलेखनीय वृद्धि हुई हैं और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या काम हुई है।

सामुदायिक विकास और कौशल प्रशिक्षणः कंपनी ने विभिन्न गांवों में 1500 सोलर लाइट और 43 हाई मास्ट सोलर लाइट स्थापित की है। इस क्षेत्र के निवासियों के सुगम पेयजल उपलब्धता हेतु 16 सौर ऊर्जा संचालित बोरवेल का निर्माण भी किया हैं। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 व्यक्तियों को मोटर चालित तिपहिया साइकिल और कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं, जिससे उनका जीवन सुगम और सुलभ हो पाया है। साथ ही स्थानीय युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 35 बैटरी संचालित तिपहिया साइकिल का वितरण किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से एचएमवी प्रशिक्षण के माध्यम से कॉमर्शियल ड्राइविंग में 27 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। कर्मियों के आवासीय सुविधा हेतु एक स्मार्ट टाउनशिप का निर्माण प्रगति पर है। उपरोक्त पहल हितधारकों के कल्याण एवं समावेशी विकास के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

ये उपलब्धियां और सीएसआर पहल, आम्रपाली-चंद्रगुप्त ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के परिचालन उत्कृष्टता और सामुदायिक विकास के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष श्री पी. एम. प्रसाद के मार्गदर्शन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सीएमडी डॉ. बी. वीरा रेड्डी के नेतृत्व से प्रेरित होकर, कंपनी ने देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के साथ - साथ श्रमिकों एवं हितधारकों के समावेशी विकास की दिशा में सफलतापूर्वक अग्रसर है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के कई अन्य प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित है

1. संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करके आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अनुकूलित करना, बर्बादी को रोकना और निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाहरी संसाधन जुटाना।

2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना व कोयले के दुर्घटना-मुक्त खनन के लिए प्रयास करना।

3. वनीकरण, पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण के नियंत्रण पर जोर देना।

4. कोयला खनन के साथ-साथ कोयला लाभकारी की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक क्षमता विकसित करना और जहां भी आवश्यक हो, कोयले के अधिक से अधिक निष्कर्षण के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य करना।

5. कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और बड़े पैमाने पर समाज और विशेष रूप से कोयला क्षेत्रों के आसपास के समुदाय के प्रति कॉर्पोरेट दायित्वों का निर्वहन करना।

6. संचालन को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल जनशक्ति प्रदान करना और कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करना।

7. भविष्य में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजनाओं की विस्तृत खोज और योजना बनाना।

8. मौजूदा खदानों का आधुनिकीकरण करना।

9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना, इत्यादि।

अबतक राजस्थान, कोलकाता एवं चेन्नई दौड़ में आगे पर हौसला सभी का बरकरार

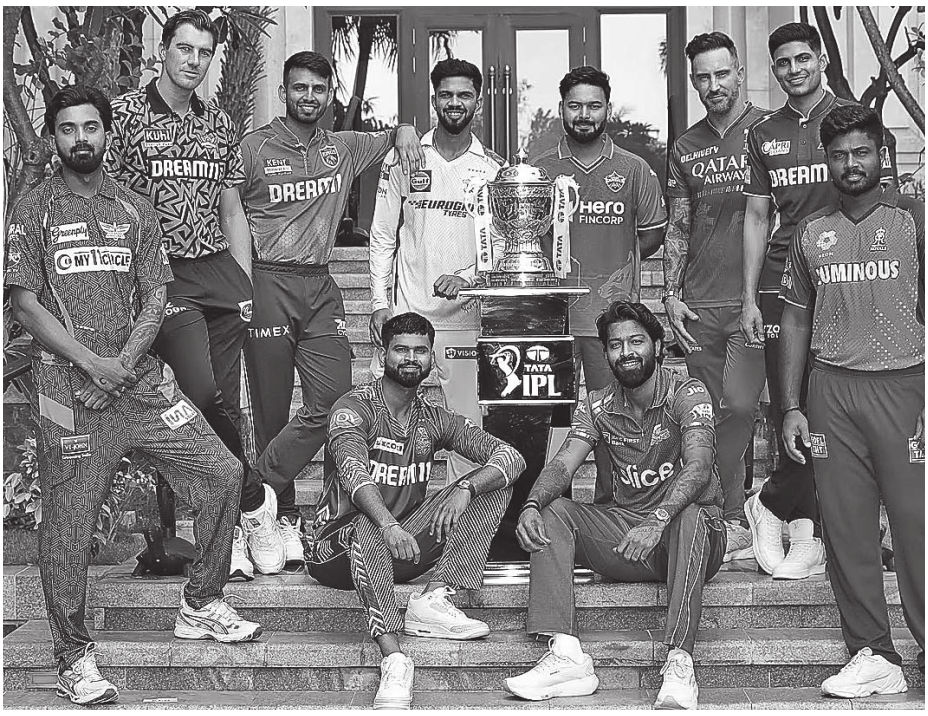

आईपीएल चैंपियन बनने की भूख सभी टीमें की पर टक्कर कांटे की

▪ चंचल भट्टाचार्य

जीत के भूखे रोहित शर्मा ने आईपीएल के मुम्बई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेले गये एक मुक़ाबले में मजबूत चेन्नई सुपर किंग्स के अनुशासित आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी. लेकिन मध्य क्रम बल्लेबाजी की कमजोरी के कारण मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने अपना शतक व्यर्थ जाते हुए देखा. मेजबान टीम हार गयी. आईपीएल 2024 के इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने उसे 20 रन से हराया. रोहित ने चेन्नई के खिलाफ 63 गेंद में नाबाद 105 रन बनाये जो उनका दूसरा आईपीएल शतक और उनके शानदार टी20 करियर का आठवां शतक है. लेकिन 18 मौकों में पहली बार, रोहित लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद रहने के बावजूद अपनी टीम को जीत दिलाने में असफल रहे. रोहित का प्रयास व्यर्थ गया क्योंकि मुम्बई की टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 186 रन पर ही सीमित रह गयी. हार्दिक पंड्या ने इस साल के आईपीएल से पहले रोहित शर्मा से एमआई की कप्तानी संभाली है. कप्तान पंड्या ने स्वीकारा कि वानखेड़े की परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई इंडियंस के लिये 207 का स्कोर हासिल करना उतना मुश्किल भी नहीं था. एमआई की यह चौथी हार थी पर अन्त में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी द्वारा दिया गया सांत्वना ही रोहित को संतोष दे पाया होगा.

शायद.यही इस साल आईपीएल की स्थिति है. लगभग सभी मैच में टक्कर कांटे की है. मुक़ाबला रोचक और नज़दीकी है. यह साल 2024 वैसे भी बहुत खास है. चुनावी मौसम है साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भी चालू है. अबकी आईपीएल सीजन में प्लेऑफ 21 मई से शुरू होंगे जबकि फ़ाइनल 26 मई को चेन्नई में खेला जायेगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले देश में आगामी आम चुनावों के कारण केवल शुरुआती 21 मुक़ाबलों का शेड्यूल जारी किया था. बाद में बीसीसीआई ने 25 अप्रैल 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 मुकाबलों के शेष कार्यक्रम की घोषणा की थी. बोर्ड ने प्लेऑफ मुकाबलों के लिये स्थानों की भी घोषणा की. चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम क्रमशः 24 और 26 मई को क्वालीफायर 2 और फाइनल की मेजबानी करेगा जबकि क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर 21 और 22 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जायेगा.

इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 के इस संस्करण में टूर्नामेंट 22 अप्रैल से 26 मई 2024 तक खेला जा रहा है जिसमें दस फ्रेंचाइजी टीमें 74 मैचों में एक दूसरे के सामने है. इस साल भारत के 13 शहरों चेन्नई, मोहाली, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, मोहाली , कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, धर्मशाला और गुवाहाटी में आईपीएल मुक़ाबले हो रहे हैं. चेन्नई उद्घाटन समारोह और फाइनल की मेजबानी करेगा.

अबकी सीजन में ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स है जबकि ग्रुप बी चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस है.

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) मौजूदा चैंपियन है जिसने पिछले सीज़न के दौरान गुजरात टाइटंस को हराकर अपना पांचवां खिताब जीता था और तब वह टूर्नामेंट के इतिहास में मुंबई इंडियंस के साथ संयुक्त रूप से सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीम बन गयी.

सीजन के पहले शेड्यूल को 22 फरवरी 2024 को घोषित किया गया था जिसमें पहले 17 दिनों का शेड्यूल शामिल था, जिसमें 21 मैच शामिल थे. टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 22 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया. शेष मुकाबलों की घोषणा 25 अप्रैल को की गई, जिसमें आखिरी ग्रुप मैच 19 मई को एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जायेगा. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस साल फाइनल चेन्नई में खेला जायेगा जहाँ 2011 के बाद यह तीसरा आईपीएल फाइनल आयोजित किया जायेगा.

इस साल दस फ्रेंचाइजी ने 2024 आईपीएल सीजन के लिये 173 खिलाड़ियों को बरकरार रखा और नीलामी से पहले सात खिलाड़ियों को टीमों में शामिल किया गया. 11 दिसंबर 2023 को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने 333 खिलाड़ियों की एक सूची जारी की, जिसमें 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे जो नीलामी के लिये उपलब्ध थे. नीलामी पहली बार भारत के बाहर संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के कोका-कोला एरिना 19 दिसंबर 2023 को आयोजित की गयी थी. नीलामी में 72 खिलाड़ी 230 करोड़ रुपये (यूएस$29 मिलियन) की कीमत पर बिके थे जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं. मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गये जब उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ (US$3.1 मिलियन) में खरीदा. वे इससे पहले इसी नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा पैट कमिंस के लिए भुगतान किये गये 20.50 करोड़ (US$2.6 मिलियन) से अधिक था.

कुल मिलाकर यदि कहा जाये तो आईपीएल मुकाबले अपनी रोमांचकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अभी अंतिम सूचना तक राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स स्कोरबोर्ड में पहले से तीसरे स्थान पर हैं. लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं है. सभी आईपीएल खिलाडी अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ हैं लेकिन 100 बात की एक बात यह भी अभी वैसे अनेक निर्णायक मुक़ाबले होनेवाले हैं जो आईपीएल के अंतिम परिणाम की तस्वीर बदल देंगे.

झारखंड को हॉकी का गढ़ बनेगा और भी मजबूत

पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग से न केवल महिला हॉकी सुदृढ़ होगी बल्कि ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी

▪ खेल डेस्क

चाहे बात मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के समय की हो या फिर आज की लेकिन एक बात सामान्य है जो दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लागू होती है। तब भी झारखण्ड हॉकी का गढ़ था और आज भी हॉकी का गढ़ है और यदि सटीक आकलन किया जाये तो आने वाले बरसों-बरस तक झारखंड की हॉकी की बादशाहत बरकरार रहेगी.

झारखंड में सभी खेलों में हॉकी तो सर्वोच्च है ही साथ ही मूल रूप में प्रमुखतः हॉकी के कारण ही पूरी दुनिया में झारखंड की पहचान है.

इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हॉकी, झारखंड की नैसर्गिक प्रतिभाओं को उभारने, आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में अपने-आप को स्थापित करने के लिए एक वैसा मंच देती है जो दूसरे किसी भी खेल के मामले में उतना अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता.

चाहे बात रांची की हो या फिर सिमडेगा, खूंटी, गुमला आदि के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की लेकिन एक बात सामान्य है। आज भले ही एस्ट्रो टर्फ़ स्टेडियम में हॉकी खेली जाती हो लेकिन झारखण्ड में हॉकी के दीवाने तभी से हैं जब यहाँ आधारभूत संरचनाओं की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ हॉकी स्टिक और बॉल तक का अभाव था। गरीबी में पलते झारखण्ड के नौनिहालों ने थेथर के डंडे या बांस की स्टिक और पत्थर-ढेला को बॉल बनाकर ऐसी कलाबाजी दिखायी कि वे झारखण्ड के गाँव-देहात से निकलकर अंतरराष्ट्रीय फलक तक छा गये.

पहले के दौर में झारखंड, केवल पुरुष हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम फहराता था। लेकिन बाद में महिला हॉकी के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति बहुत मजबूत हो गयी। यहाँ तक कि ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेनेवाली भारतीय टीम में अनेक महिला खिलाड़ी झारखंड से ही होती हैं। यह श्रृंखला विशेष रूप से तब से और भी मजबूत हुई जब से हॉकी इंडिया ने नये प्रबंधन और अपनी प्रोफेशनल मानसिकता के साथ अपना विस्तार करना शुरू किया। इसका बहुत अधिक सकारात्मक फायदा यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों और देश भर के हॉकी केन्द्रों को हुआ है। भारत की प्रतिष्ठा हॉकी के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ी है। हॉकी इंडिया की सबसे खास बात यह भी रही कि इसने मूल रूप से हॉकी की नर्सरी झारखण्ड, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में अपने आधार को और भी मजबूत करने का प्रयास किया। आज उड़ीसा और झारखंड, दो ऐसे प्रदेश हैं जो भारतीय हॉकी के परचम को पूरी दुनिया में फहराने की कुबत रखते हैं। इसके साथ ही पंजाब, आंध्र प्रदेश या अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपने खेल कौशल और अनुभव के बलबूते भारतीय हॉकी को एक नयी पहचान दी है चाहे बात पुरुष हॉकी की हो या फिर महिला हॉकी की.

वैसे तो रांची या झारखण्ड, हॉकी के लिये एक स्वाभाविक नर्सरी है जहां प्राकृतिक परिवेश में हॉकी का जमकर विकास होता है। झारखण्ड की जमीन ही ऐसी है जहाँ हॉकी के खिलाड़ी उत्प्रेरित होते हैं। लेकिन विशेष रूप से भोलानाथ सिंह के हॉकी झारखंड का अध्यक्ष बनने एवं हॉकी इंडिया के महासचिव के रूप में दायित्व संभालने के बाद रांची को हॉकी के क्षेत्र में और भी ख्याति प्राप्त हुई है और झारखंड के खिलाड़ियों को नई उड़ान भरने में बहुत गति आयी है.

कुछ महीने पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था जिसमें 6 देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया। रांची में पहली बार आयोजित इस टूर्नामेंट में हांगझोऊ एशियाई खेल के चैंपियन चीन और रजत पदक हंगरी के साथ ही मलेशिया, जापान और मेजबान भारत ने भाग लिया और सबसे दिलचस्प स्थिति यह रही कि भारतीय टीम न केवल चैंपियन बनी बल्कि सभी मुकाबले में वह अपराजेय रही और उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को पराजित किया.

इसके तत्काल बाद झारखंड और रांची में ही भारत की मेजबानी में ओलंपिक क्वालीफायर मैच का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अमेरिका, जर्मनी, जापान, चिली, चेक रिपब्लिक, इटली, न्यूजीलैंड के साथ ही शीर्ष वरीयता क्रम में दुनिया की छठे नंबर की टीम मेजबान भारतीय टीम ने भाग लिया। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त तीन देशों ने पेरिस में 2024 में होनेवाली ओलंपिक में भाग लेने का टिकट पक्का किया। बहुत हद तक अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही और शीर्ष तीन स्थान में अपने-आपको कायम करने से चूक गयी। भारत क्वालीफाई तो नहीं कर सका परन्तु कुल मिलाकर भारत की मेजबानी की सभी ने तारीफ की और झारखंड के साथ ही रांची को हॉकी के बेहद महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्वीकार किया.

और अब फिर से एक महत्वपूर्ण मौका है। अगले 30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक भारत में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय महिला घरेलू हॉकी लीग का आयोजन किया गया है। पहली नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 की मेजबानी का मौका झारखंड को मिला है। इसमें देशभर की आठ महत्वपूर्ण हॉकी टीम भाग लेंगी। इसमें हॉकी हरियाणा, हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी बंगाल, हॉकी मिजोरम, मणिपुर हॉकी और हॉकी एसोसिएशन ऑफ़ ओडिशा के साथ ही मेजबान हॉकी झारखंड की टीम शामिल है। रांची में लीग मैचों के आयोजन के साथ ही विश्वास यही है कि, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में झारखंड के दर्शकों के साथ ही पूरे देश के हॉकी प्रेमियों को भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से रोमांचक हॉकी देखने का अवसर मिलेगा। वास्तव में यह मौका बहुत ही खास है और झारखंड और रांची के परिप्रेक्ष्य में इस अवसर को स्वर्णिम कहना कहीं अधिक बेहतर होगा। एक ओर लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है और इसी दौरान जब 30 अप्रैल से रांची में महिला हॉकी का जलवा बिखरना शुरू होगा तो फिर क्या कहने..। यह सोने पर सुहाग वाली बात होगी और विशेष रूप से रांची और झारखंड की मेजबानी के साथ ही हॉकी झारखण्ड को राष्ट्रीय फलक पर अपनी दूरगामी पहचान कायम करने के साथ ही झारखण्ड के गाँव-देहात में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों... उससे भी अधिक बच्चों के बीच हॉकी के क्रेज को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यह हॉकी के संपूर्ण विकास और न जाने ऐसी कितनी बातों के लिये यह अभूतपूर्व मौका है.

'छावा' के सेट से सामने आया विक्की का लुक

विक्की इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'छावा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में विक्की, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाते नजर आएंगे।

फिल्म के सेट से विक्की की छत्रपति संभाजी महाराज के लुक में कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में विक्की स्लीवलेस कुर्ता और धोती पहने नजर आ रहे हैं। वो माथे पर त्रिपुंड धारण किए और गले में रुद्राक्ष की माला पहने दिख रहे हैं। इस फिल्म में संभाजी महाराज की वीरता, साहस, बलिदान और सैन्य रणनीतियों के अलावा पत्नी के साथ उनकी मार्मिक प्रेम कहानी भी पेश की जाएगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना संभाजी महाराज की पत्नी येसूबाई भोंसले का किरदार निभाएंगी।

रश्मिका मंदाना ने इस साल 27 जनवरी को इस फिल्म के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया था।

रवीना ने ठुकराया था 'कुछ कुछ होता है' का ऑफर

1998 में रिलीज हुई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' उन दिनों की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने बताया कि इस फिल्म में उन्हें रानी मुखर्जी का रोल ऑफर किया गया था। उन्होंने इस रोल को करने से साफ इंकार कर दिया था। उनका कहना है कि उन दिनों मेरा करियर बहुत ऊंचाई पर था। मैं इस तरह का छोटा रोल नहीं करना चाह रही थी। वहीं रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके लिए वो रोल करना अच्छा साबित हुआ। क्योंकि वो इंडस्ट्री में नई थीं।

हेमा को राजनीति में नहीं आने देना चाहते थे धर्मेंद्र

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और बेहतरीन क्लासिकल डांसर हेमा मालिनी आजकल लोकसभा इलेक्शन में जोर-शोर से प्रचार करती नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनका पॉलिटिकल करियर भी उतना ही सक्सेसफुल रहा जितना कि बॉलीवुड करियर। अमिताभ बच्चन से लेकर कई दिग्गज पॉपुलर सितारों ने बॉलीवुड के अलावा पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाई।

एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी बताया की 'धरमजी को ये बिलकुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चुनाव न लड़ूं क्योंकि ये बहुत कठिन टास्क है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर लिया।' हेमा बोलीं, 'धरमजी को राजनीति में इसलिए दिक्कत आई क्योंकि उन्हें ट्रैवल काफी करना पड़ता था और इसके साथ उन्हें फिल्मों में भी काम करना था।' हेमा ने आगे कहा, 'जब आप एक फिल्म स्टार होकर राजनीति में आते हैं तो लोगों का क्रेज आपके प्रति और बढ़ जाता है। धरमजी को लेकर फैंस का क्रेज सब जानते हैं तो उन्हें इसे मैनेज करने में काफी दिक्कत होती थी। मैं भी कई परेशानियों का सामना करती हूं जो धरमजी को बिलकुल पसंद नहीं लेकिन मैं एक महिला हूं तो मैं ठीक से सबकुछ मैनेज कर लेती हूं। '

हेमा ने बताया कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी में विनोद खन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेमा बोलीं, मैं विनोद खन्ना से प्रभावित थी क्योंकि वो मुझे अपनी चुनावी सभाओं में साथ ले जाते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जैसे स्पीच कैसे देना है, पब्लिक को कैसे फेस करना है आदि। पांच-छह हजार लोगों के सामने स्पीच देना कोई मजाक की बात नहीं है। आप पहली बार में डर जाते हैं।

राशिफल

मेष मई के महीने के आरंभ में शुक्र वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। इससे मिथुन राशि में शुक्र मंगल का संयोग बनेगा। हालांकि मंगल 10 मई को कर्क राशि राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के अलावा मई के महीने में सूर्य भी राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आएंगे और मंगल मेष राशि में उदित होकर मार्गी गति से संचार करेंगे।

मिथुन सिंह राशि के लोगों को ग्रह गोचर के इस शुभ प्रभाव से विशेष सफलता हासिल हो सकती है और करियर से संबंधित मामलों में आपको लाभ होगा। इस वक्त जॉब के कुछ नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। व्यापार करते हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। करियर के लिहाज से महीना शुभ लाभदायक रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

सिंह सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिलाजुला साबित होने वाला है। माह की शुरुआत में घरेलू परेशानियों के साथ कार्यक्षेत्र से जुड़े कामकाज को समय पर पूरा करने का दबाव बना रहेगा। इस दौरान इष्टमित्र की मदद भी न मिल पाने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा। जो लोग रोजी-रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

तुला तुला राशि के लिए मई के महीने में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। किसी के बहकावे में आकर किसी योजना में धन निवेश न करें और न ही कोई कोई बड़ा निर्णय लें। माह की शुरुआत में घर की मरम्मत या सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों के लिए जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है।

धनु जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते समय आप कई बार खुद को अकेला पाएंगे, लेकिन बावजूद इसके आपकी समस्याओं का समाधान आखिरकार निकल ही आएगा। कार्यक्षेत्र में कामकाज का अधिक बोझ बना रहेगा। इस दौरान आपको कार्य विशेष को पूरा करने के लिए श्रम व समय की जरूरत रहेगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आप जरूरत से ज्यादा अपने लव पार्टनर की जिंदगी में दखल देने से बचें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है।

कुंभ माह की शुरुआत में घर-परिवार की जरूरतों पर जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है। इस दौरान मकान या किसी महंगे सामान आदि की मरम्मत आदि पर बड़ी धन राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कामकाज का बोझ बना रहेगा। विशेष रूप से पेशेवर महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

वृषभ मिथुन राशि के लिए मई में होने वाले ग्रह गोचर से करियर के मामले में विशेष लाभ होने जा रहा है। आपको इस वक्त मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन इससे आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होने से कई अधूरे कार्य पूर्ण होंगे।

कर्क कर्क राशि के जातकों के लिए मई माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा बेहतर रहने वाला है। ऐसे में मई माह के पूर्वार्ध में आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि आप लोगों की छोटी-मोटी बातों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करें।

कन्या कन्या राशि के जातकों के लिए मई माह जिंदगी में नए और बेहतर अवसर लेकर आएगा। माह की शुरुआत में ही आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। इस दौरान सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकता है, हालांकि आपकी आय के नए स्रोत भी बढ़ेंगे और संचित धन में वृद्धि भी होती रहेगी।

वृश्चिक वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मई का महीना करियर के मामले में शुभ फल देने वाला होगा। बॉस और सहयोगियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। करियर के लिहाज से भी यह समय आपके लिए तरक्की देने वाला हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वक्त आपको मनपसंद प्रस्ताव मिल सकते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता से जुड़े खिलाड़ियों के लिए यह महीना सबसे शानदार होगा।

मकर मकर राशि के जातकों को इस महीने ग्रहों के गोचर से बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मन के अनुसार कार्य करने को मिलेंगे। बॉस के साथ पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी और विदेशी संस्थाओं के साथ कार्य में संभलकर चलें। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

मीन मीन राशि वालों के लिए मई के महीने में होने वाले ग्रहों के बदलाव बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले होंगे। करियर और प्रतियोगिता में आप आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। नए संपर्क बनेंगे और लाभ मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और बाहरी स्रोतों से भी फायगा होगा। पारिवारिक मामलों में भी यह महीना सबसे शानदार होगा। यह महीना आपके लिए कहीं से अचानक धन प्राप्ति वाला भी हो सकता है।

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजली तेंदुलकर के साथ रांची पहुंचे। यहां उन्होंने फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यहां फुटबॉल खेलने वाले जूनियर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आया हूं। सचिन ने ओरमांझी में युवा फाउंडेशन का दौरा किया। यहां बच्चों से मुलाकात की। उनके साथ खेलते, मस्ती करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में काम करता है। हम युवा फाउंडेशन का सहयोग कर रहे हैं। बच्चों को खेलते हुए देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। इनके साथ मैंने जन्मदिन का केक भी काटा।

नाल्को ने उत्पादन व बिक्री के क्षेत्र में बनाया नया रिकॉर्ड

अब तक का सबसे अधिक एल्यूमीनियम और बॉक्साइट उत्पादन हासिल किया

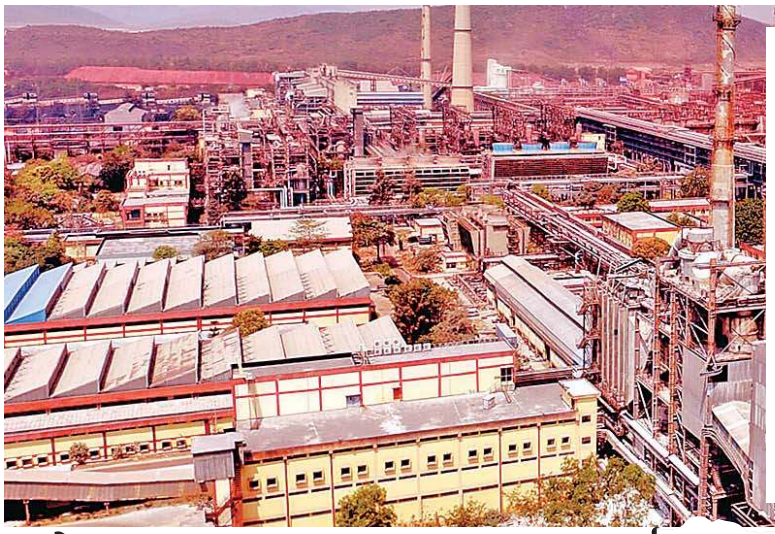

प्रदर्शन की मुख्य बातें

4,63,428 मीट्रिक टन का अब तक का सर्वाधिक कास्ट मेटल उत्पादन

4,70,108 मीट्रिक टन का अब तक का सर्वाधिक धातु की बिक्री

76,00, 230 मीट्रिक टन का अब तक का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन

2 मिलियन टन उत्कल डी कोयला ब्लॉक से कोयले की उच्चतम रेटेड क्षमता पर विकास और उत्पादन

नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), खान मंत्रालय, सरकार के तहत प्रमुख नवरत्न सीपीएसई। भारत की, और देश की अग्रणी एल्यूमिना और एल्युमीनियम निर्माता और निर्यातक ने वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादन और बिक्री में नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

कंपनी ने स्थापना के बाद से अब तक के सभी पिछले रिकॉर्डों को पार करते हुए 4,63,428 मीट्रिक टन का उच्चतम कास्ट मेटल उत्पादन, 76,00,230 मीट्रिक टन का उच्चतम बॉक्साइट उत्खनन और 4,70,108 मीट्रिक टन की सबसे अधिक धातु बिक्री हासिल की है। वित्त वर्ष 23-24 में कंपनी ने अपने उत्पाद रेंज में एक नया एल्युमीनियम अलॉय इनगॉट (AL-59) भी जोड़ा है।

101.15% क्षमता उपयोग हासिल करते हुए, नाल्को की एल्यूमिना रिफाइनरी ने 21,24,000 मीट्रिक टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन किया है, जबकि कैप्टिव पावर प्लांट ने सकल 7193.62 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 23-24 में, नाल्को ने अपने उत्कल डी कोयला ब्लॉक का विकास और संचालन किया है और 2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन भी किया है, जो खदान की सर्वोच्च रेटेड क्षमता है। नाल्को के सीएमडी श्री श्रीधर पात्रा ने कहा कि कंपनी ने हमेशा पिछले निर्धारित मानकों से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने नाल्को समूह और हितधारकों को बधाई दी। कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सहयोग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में कच्चे माल और ऊर्जा के पिछड़े एकीकरण और प्रतिभूतिकरण के माध्यम से कई प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए गए हैं।

श्रद्धा महिला मण्डल की अध्यक्ष पूनम को शिल्पा शेट्टी के हाथों मिला सम्मान

श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष व एसईसीएल परिवार की प्रथम महिला श्रीमती पूनम मिश्रा ने प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के हाथों सम्मान ग्रहण किया है। समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए श्रद्धा महिला मंडल को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह सम्मान प्रदान किया गया।